वर्ष-11, अंक-2, नवंबर-2025

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

बिहार में ऐतिहासिक जीत

मोदी का कोई तोड़ नहीं

खुशहाल किसान
उत्तर प्रदेश की पहचान

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत
धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार खरीद
वर्ष 2025-26

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सीधे किसानों से धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार खरीद की जा रही है।

इस वर्ष धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार की बिक्री हेतु एकल पंजीकरण की व्यवस्था, खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक किसानों को ही दिलाने हेतु पारदर्शी ऑनलाइन खरीद की व्यवस्था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

धान (कॉमन) ₹2,369/- प्रति क्विंटल
धान (ग्रेड-ए) ₹2,389/- प्रति क्विंटल
मक्का ₹2,400/- प्रति क्विंटल
बाजरा ₹2,775/- प्रति क्विंटल
ज्वार (हाइब्रिड) ₹3,699/- प्रति क्विंटल
ज्वार (मालदाण्डी) ₹3,749/- प्रति क्विंटल

मक्का खरीद हेतु 25 जनपदों में 117 केंद्र स्थापित

बाजरा खरीद हेतु 33 जनपदों में 279 केंद्र स्थापित

ज्वार खरीद हेतु 11 जनपदों में 78 केंद्र स्थापित

धान खरीद हेतु 4000 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद का लक्ष्य

किसान भाइयों से अपील

अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने हेतु अपनी फसल की बिक्री राजकीय क्रय केंद्र पर करें और योजना का लाभ उठाएं।

17% तक नमी का धान खरीदा जा सकता है, अतः धान को अच्छी तरह सुखाकर, साफ कर खरीद केंद्र पर लाएं।

किसान भाई अपना आधार कार्ड अद्यतन रखें एवं वर्तमान में उपयोग किए जा रहे मोबाइल नम्बर को ही आधार कार्ड से लिंक कराएं।

1. किसान भाई अपना व्यक्तिगत विवरण/सूचना यथा-भूलेख विवरण/खतौनी, आधार संख्या, मोबाइल नम्बर, कृषक पंजीकरण में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर में प्राप्त ओटीपी इत्यादि किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।
2. किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाना है। किसान भाई अपनी बैंक शाखा से सम्पर्क कर अपना आधार एन.पी.सी.आई. पोर्टल पर अवश्य मैप करा लें।
3. किसान पंजीकरण में गाटावार विवरण के अनुसार एग्रीस्टैक एवं ई-पड़ताल के डाटा का प्रयोग करके आटोमेटेड सत्यापन की व्यवस्था की गयी है।

कृषक किसी भी सहायता एवं जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या संबंधित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष- 11 अंक- 2

नवंबर-2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

अन्दर के पेजों में...

अपराध कतई स्वीकार नहीं करता नया यूपी: मुख्यमंत्री योगी — पेज 05

लाल किला विस्फोट के बाद उठते गंभीर सवाल — पेज 10

बीजेपी यूपी-बंगाल में भी महिलाओं युवाओं पर लगाएगी दांव — पेज 20

प्रदूषण की कीमत: क्या भारत को चाहिए एक व्यापक 'प्रदूषण कर'? — पेज 39

बॉलीवुड की फेमस अदाकारा सुष्मिता सेन, 18 की उम्र में ही बन गई थीं मिस यूनिवर्स — पेज 53

रोहित शर्मा से छीनी बादशाहत, किवी खिलाड़ी मिशेल बने नंबर वन — पेज 54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 / 9813221734 पर सम्पर्क करें।

विपक्ष का समर्थन वोटों में क्यों नहीं बदल सका

ललित कुमार
सम्पादक

बिहार में विधानसभा के लिए हुए चुनावों के नतीजे निश्चित तौर पर वहां की जनता का फैसला है, लेकिन हार-जीत के जैसे आंकड़े सामने आए, उसकी उम्मीद कम से कम वहां के विपक्षी दलों को बिल्कुल नहीं रही होगी। दो चरणों में हुए मतदान के बाद शुक्रवार को हुई मतगणना में न केवल सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी जीत मिली, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी मैदान में मुकाबला एकतरफा था। हालांकि प्रचार के दौरान विपक्षी महागठबंधन को जैसा समर्थन मिलता दिखा था, उससे यही लगा कि चुनावी मुकाबला एकतरफा साबित नहीं होने वाला है और राजद-कांग्रेस तथा अन्य सहयोगी दलों का महागठबंधन चुनाव में राजग को एक मजबूत चुनौती देने वाला है। मगर अब आए नतीजों से यह साफ है कि बिहार के चुनावी मैदान में मतदाताओं को आकर्षित करने और उनका मत हासिल करने के मामले में सत्ताधारी गठबंधन के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। दूसरी ओर, विपक्ष की राजनीति और विधानसभा चुनावों में जीत के लिए किए गए प्रयासों के लिहाज से देखें तो ये नतीजे उनके लिए अप्रत्याशित हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान सभाओं और रैलियों में उन्हें लोगों का जैसा व्यापक समर्थन मिलता दिखा था, वह शायद वोट में तब्दील नहीं हो सका। सवाल है कि विपक्ष की राजनीति के महारथी जनता के बीच दिखने वाले समर्थन के बरक्स जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाने में नाकाम क्यों हुए! माना जा रहा है कि राज्य के मतदाताओं के सामने अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से जो कुछ तात्कालिक लाभ के मुद्दे सामने रखे गए, लोगों ने उसी में से चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकता तय की। मसलन, एक ओर बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में तत्काल दस हजार रुपए भेजने की व्यवस्था की, तो दूसरी ओर, महागठबंधन ने हर परिवार के लिए सरकारी नौकरी सहित कई अन्य वादे किए। ऐसा लगता है कि राज्य के लोगों की राय पर भविष्य के लिए किए गए वादों के बजाय महिलाओं को तुरंत मिली आर्थिक राहत का मुद्दा ज्यादा भारी पड़ा और उसने चुनाव में मतदान के रुख को तय करने में एक प्रमुख कारक के रूप में काम किया। राजद और उसके सहयोगी दल शायद जनता को यह भरोसा दिला पाने में कामयाब नहीं हो सके कि सरकार बनने पर उनके वादे वास्तव में जमीन पर उतर सकेंगे। इसके अलावा, बिहार में इस बार मतदान का जैसा आंकड़ा सामने आया, वह भी चौंकाने वाला था। जब दोनों चरणों में लगभग सड़सठ फीसद वोट पड़े, तब स्वाभाविक रूप से ऐसे आकलन सामने आने लगे कि इतना मतदान फीसद आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर का संकेत देते हैं। मगर अब जैसे नतीजे सामने आए हैं, उसमें ज्यादा मत पड़ने के साथ जुड़ी सत्ता विरोधी लहर की धारणा एक तरह से खारिज होती दिखी। अब बिहार के मतदाताओं ने एक बार फिर से राजग सरकार के कामकाज और उससे पैदा उम्मीदों को अपना भारी समर्थन दिया है, वहीं विपक्षी दलों और खासतौर पर राजद के सामने आने वाले दिनों में अपनी पार्टी के मजबूत दखल को बचा पाने तक की चुनौती सामने होगी। मगर उम्मीद की जानी चाहिए कि स्पष्ट बहुमत के साथ बनने वाली सरकार के कामकाज आम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख कर संचालित होंगे और राजनीतिक मोर्चे पर राज्य में लोकतंत्र का जीवन पहले से ज्यादा बेहतर होगा।

ऐसा लगता है कि राज्य के लोगों की राय पर भविष्य के लिए किए गए वादों के बजाय महिलाओं को तुरंत मिली आर्थिक राहत का मुद्दा ज्यादा भारी पड़ा और उसने चुनाव में मतदान के रुख को तय करने में एक प्रमुख कारक के रूप में काम किया। राजद और उसके सहयोगी दल शायद जनता को यह भरोसा दिला पाने में कामयाब नहीं हो सके कि सरकार बनने पर उनके वादे वास्तव में जमीन पर उतर सकेंगे।

वंदे मातरम् की गौरव गाथा

प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम्ा की गौरव गाथा को विभिन्न उपमाओं-अलंककरणों से स्पंदन देते हुए इससे जुड़े इतिहास के एक काले पन्ने को खोलने के साथ कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की विभाजनकारी मानसिकता का खुलासा बिना किसी का नाम लिए किया।

वंदे मातरम्ा को भारत की शाश्वत संकल्पना बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ विशेष डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ किया। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् की गौरव गाथा को विभिन्न उपमाओं-अलंककरणों से स्पंदन देते हुए इससे जुड़े इतिहास के एक काले पन्ने को खोलने के साथ कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की विभाजनकारी मानसिकता का खुलासा बिना किसी का नाम लिए किया।

उन्होंने कहा कि 'आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम् की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाषित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में इस गीत के

संजीव कुमार

महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। जिस भाव से वंदे मातरम् के टुकड़े किए गए थे, कालांतर में उसी भाव ने विभाजन के बीज बो दिए थे।' अतीत में इस गीत की मूल रचना के साथ जो भी खिलावाड़ किया गया हो, किंतु यह सच्चाई है कि आजादी की लड़ाई में इस गीत की अहम्-भूमिका रही है।

बंकिमचंद्र चटर्जी के बांग्ला भाषा में लिखे उपन्यास 'आनंद मठ' से राष्ट्रगीत के रुप में स्वीकारा गया यह गीत कोई मामूली गीत नहीं है। भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रीयता की पहचान और स्वाभिमान इसी गीत से प्राप्त हुए। नागरिक सभ्यता की विरासत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव सेवा के मूल्यों के उत्स इसी गीत के समवेत स्वर की उपज हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भिन्न जातीय और धर्म-समुदायों को संगठित करने के अभियान में इसी गीत की भूमिका बुलंद थी। तय है, वंदे मातरम् क्रांति के स्वरों में नींव का पत्थर था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रक्त धमनियों में विद्रोह की उग्र भावना इसी गीत की देन है। 1942 में महात्मा गांधी के

भारत छोड़ो आंदोलन को देषव्यापी धरातल इसी गीत के बूते मिला था। और वह यही आंदोलन था, जिसमें गांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया था। सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज के फौजियों ने भी इसी गीत को गाते हुए मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर किए।

14 अगस्त 1947 की मध्य-रात्रि में जब देष आजाद हो रहा था, तब इस मंत्र-गीत का गायन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया और वहां उपस्थित लोग इस गीत के सम्मान में गीत खत्म न हो जाने तक खड़े रहे। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता का सूर्योदय हो रहा था, तब आकाषवाणी पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से गाया। आखिरकार 24 अगस्त 1948 को जन-गण-मन के साथ इस गीत को भी राष्ट्र गीत की प्रतिष्ठा मिली। लेखक और दार्शनिक युगद्दष्टा होते हैं, इसलिए बंकिम बाबू ने इस गीत को लिखे जाने के वक्त ही अपनी दिव्य-द्दष्टि से अनुभव कर लिया था कि यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर लोकप्रियता के शिखर चूमेगा, इसीलिए उन्होंने इसे बांग्ला भाषा में न लिखते हुए संस्कृत में लिखा। मूल और संपूर्ण गीत की केवल नौ पंक्तियां बंगाली में हैं। इस गीत का जो संपादित अंश राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है, वह केवल आठ पंक्तियों का है। वंदे मातरम् को इस्लाम विरोधी जताया जाता रहा है। जब कांग्रेस ने इसे प्रार्थना गीत के रुप में स्वीकार किया था, तब भी इसकी खिलाफत हुई थी। 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसमें मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे प्रखर संस्कृति मर्मज्ञ सदस्य थे। समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे रवीन्द्रनाथ ठाकुर से विचार-विमर्श कर वंदे मातरम् के संबंध में दो टूक सलाह दें। समिति द्वारा रवीन्द्रनाथ से परामर्ष के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि हरेक राष्ट्रीय व सार्वजनिक सभा में वंदे मातरम् के केवल दो पद गाये जाएं। ऐसे अवसरों पर भारत विभाजन के जनक मोहम्मद अली जिन्ना भी इस गीत को आदर के साथ खड़े होकर गाया करते थे। तय है, गीत पर विवाद का समाधान स्वतंत्रता से पहले ही हो चुका था।

बाद में देश-विभाजन के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग के नेताओं ने जरूर वंदे मातरम् को बुतपरस्ती, अर्थात मूर्तिपूजा मानते हुए इसका विरोध किया। इस बहाने लीगियों ने अल्पसंख्यकों को खूब उकसाया। नतीजतन 1938 तक कांग्रेस के जो प्रमुख मुस्लिम नेता इस गीत की राष्ट्रीय गरिमा का ख्याल रखते चले आ रहे थे, वे भी दबी जुबान से इसका विरोध करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुसंख्यक हिंदू और सिख हठपूर्वक इस गीत की महिमा के बखान में लगे रहे। बाद में साझा सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के नजरिये से उर्दू के उदारवादी कवियों व राजनीतिकों ने वंदे मातरम् का अनुवाद 'ऐ मादर, तुझे सलाम करता हूं' किया, अर्थात हे माता, तुझे प्रणाम करता हूं। मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की इस इबादत में गलत क्या है ? अरबी फारसी के अनेक कवियों ने भी देष को 'मां' कहकर संबोधित किया है। लिहाजा राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं व उद्गारों को प्रचलित रूपकों अथवा प्रतीकों में प्रकट करना मूर्तिपूजा या बुतपरस्ती कतई नहीं है। वंदे मातरम् एक मौलिक रचना है, इसकी व्याख्या धर्म नहीं, केवल साहित्य के संदर्भ में होनी चाहिए। इसे यदि कोई सांसद या विधायक इस्लाम विरोधी जताता है, तो उसका मकसद धर्म के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकना है, जो अलगाववादी राजनीति की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है।

खुद बंकिमचन्द्र ने लिखा है कि 'हिन्दू होने पर ही कोई अच्छा नहीं होता है, मुसलमान होने पर कोई बुरा नहीं होता और न ही मुसलमान होने पर कोई अच्छा होता है या हिन्दू होने पर कोई बुरा होता है। अच्छे बुरे दोनों जातियों में हैं। गोया, निर्वाचित चंद मुसलिम प्रतिनिधि इस्लाम के बहाने जिस राश्ट्रीयता का अपमान करते हैं, उसी राश्ट्रीयता के सम्मान में अन्य मुस्लिम प्रतिनिधि सुर में सुर मिलाते हैं। ऐसे ही चंद सिरफिरे मुस्लिमों ने आजाद हिंद फौज के नारे, 'जय हिंद' का भी विरोध किया था, जब दैनिक अखबार 'डान' ने वंदे मातरम् की आलोचना की तो महात्मा गांधी को कहना पड़ा, 'वंदे मातरम् कोई धार्मिक नारा नहीं है, यह विशुद्ध राजनीतिक नारा है।' यही नारा था, जिसने सोये हुए भारत को जगाने का काम करके, आजादी हासिल कराई थी।

अपराध कतई स्वीकार नहीं करता नया यूपी: सीएम योगी

- अपराध करने वालों को चुकानी ही होगी कीमत : सीएम योगी
- बी से ए क्लास में उच्चीकृत हुई गोरखपुर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- 72.78 करोड़ रुपये की परियोजना का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण
- मॉडर्न पुलिस के लिए गेम चेंजर बनेगी फॉरेंसिक साइंस लैब इन मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद का नया उत्तर प्रदेश अपराध को कतई स्वीकार नहीं करता है। यदि किसी ने यहां अपराध करने की जुर्रत की तो उसे हर हाल में उसकी कीमत भी चुकानी होगी। वह दौर खत्म हो गया जब पीड़ित तड़पता, भटकता था और अपराधी मौज-मस्ती करते थे। अब प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत साक्ष्य संकलन और फॉरेंसिक साइंस लैब्स (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) के जरिए इसके प्रमाणन की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश

उज्जवल रस्तौगी

सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित जांच और आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब्स के जरिए ऐसी व्यवस्था विकसित हुई है कि अपराधी अब बच नहीं सकते। सटीक, त्वरित और पारदर्शी जांच के कारण पीड़ित को सहज, सुगम और समयबद्ध न्याय उपलब्ध हो रहा है। सीएम योगी मंगलवार को बी से ए क्लास में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) गोरखपुर के नवीन उच्चीकृत भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। छह मंजिला हाईटेक नवीन भवन के निर्माण पर 72.78 करोड़ रुपये की लागत आई है। उच्चीकृत आरएफएसएल का फीता काटकर उद्घाटन करने और यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने फॉरेंसिक जांच की अत्याधुनिक सौगात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि आबादी के

मॉडर्न पुलिस के लिए गेम चेंजर बनेगी फॉरेंसिक साइंस लैब

सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जो सटीक जांच करेंगी। यह लैब मॉडर्न पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। त्वरित और पुख्ता जांच होने से लोगों को समय से सुसंगत न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का ही हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर की यह उच्चीकृत लैब उन चुनिंदा संस्थानों में शामिल होगी जहां बैलेस्टिक, नार्कोटिक्स, सेरोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक, डीएनए प्रोफाइलिंग, डाक्यूमेंट विश्लेषण से लेकर सभी उन्नत फॉरेंसिक परीक्षण संभव होंगे। ऐसी क्षमता से पुलिस के कार्य में गति, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य साइबर फॉरेंसिक को वैश्विक मानक तक पहुंचाना है ताकि भविष्य में होने वाले हाईटेक अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

फॉरेंसिक साइंस लैब्स से रोजगार का सृजन भी होगा

सीएम योगी ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब्स से युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी होगा। इसके लिए सरकार ने लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की है। यहां लैब टेक्नीशियन के लिए सर्टिफिकेट, लैब में साक्ष्य मिलान करने वालों के लिए डिप्लोमा और विशेषज्ञ के लिए डिग्री कोर्स शुरू किए गए हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब्स नए समय में नए अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक, एआई, ड्रोन, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। यहां नैनो से लेकर 40 किलो वजनी ड्रोन संचालित किए जा सकते हैं।

लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ चार फॉरेंसिक साइंस लैब थे। सरकार बनने के बाद यह तय किया गया कि कम से कम हर कमिश्नरी में एक फॉरेंसिक साइंस लैब होनी चाहिए। इससे आठ वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। छह लैब निमार्णाधीन हैं। जल्द ही सभी कमिश्नरी में फॉरेंसिक साइंस लैब होंगे। इन लैब्स में हर प्रकार की फॉरेंसिक जांच होगी जो साक्ष्य को प्रमाणित कर अपराधियों को कठोर दंड दिलाने का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कमिश्नरी स्तर पर फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने के साथ सरकार ने हर जिले में फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन के लिए दो-दो मोबाइल वैन उपलब्ध कराए हैं। इससे कुछ ही घंटों में पुख्ता साक्ष्य संकलन हो जा रहा है और लैब में उसकी जांच के बाद पीड़ित को सहज और सुगम न्याय मिल जाएगी। अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले साक्ष्य इकट्ठे होने पर भी अच्छी फॉरेंसिक साइंस लैब के अभाव में अपराधी बच जाते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गत वर्ष जुलाई से तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023) लागू होने के बाद फॉरेंसिक साइंस लैब्स की उपयोगिता और बढ़ गई है। नए कानून में सात वर्ष से अधिक कारावास वाले

अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है। इन कानूनों के लागू होने से काफी पहले ही यूपी सरकार ने लैब्स स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी थी।

आठ वर्षों में की 2.19 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रूल ऑफ लॉ को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इसे लागू करने प्रयासों के तहत आठ सालों में प्रदेश में 2 लाख 19 हजार पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई है। इसमें 60244 कार्मिकों की भर्ती हाल ही में संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि आठ वर्षों में यूपी में जितनी पुलिस भर्ती हुई है, उतनी कई राज्यों की कुल पुलिस फोर्स नहीं है। सीएम ने भर्ती के साथ ट्रेनिंग क्षमता विस्तार का भी उल्लेख किया। कहा कि 2017 में पुलिस ट्रेनिंग की कुल क्षमता 6000 की थी। तब 30000 भर्ती होने पर किराए पर ट्रेनिंग सेंटर लेने पड़े थे। आज प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता दस गुने से अधिक बढ़ चुकी है। अभी जितनी भर्ती हुई, सबको ट्रेनिंग राज्य के ही सेंटर्स से मिल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में सरकार कार्य के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अभी जिलों में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखेगी, वह पुलिस बैरक की होगी।

50 साल पुरानी थी कमिश्नरेट सिस्टम की मांग

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम की मांग 50 साल पुरानी थी। 2020 में उनकी सरकार ने इसे पूरा किया। प्रदेश के सात जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। उन्होंने कहा इसके साथ ही सरकार ने 17 नगर निगम और नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी बनाने का कार्य किया है। 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाकर महानगरों को सुरक्षित किया गया है।

कुछ ही घंटे में शिकंजे में, लंगड़ाता दिखेगा अपराधी

सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निगरानी प्रणाली से घटना के कुछ ही घंटे में अपराधी शिकंजे में होगा। वह लंगड़ाते दिखेगा। सबको सुरक्षा और सबको सम्मान के भाव से काम करने वाले आज के यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

पिछली सरकारों ने की पीएसी को समाप्त करने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पीएसी की बटालियन को समाप्त करने की कोशिश की। उनकी सरकार ने इसे बचाया है। इसके साथ ही एसएसएफ, एसडीआरएफ के साथ पीएसी की तीन महिला बटालियन स्थापित की। इसमें गोरखपुर में पीएसी की महिला बटालियन वीरांगना झलकारी बाई, लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर स्थापित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पांच जिलों बलरामपुर, जालौन, मिजार्पुर, शामली और बिजनौर में नई पीएसी बटालियन बनाने का भी कार्य किया। दस जिलों में अत्याधुनिक पुलिस लाइन बनाने के लिए धनराशि दी।

सुरक्षा के माहौल में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में पहले असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी कम थी। 2017 के पहले यह 13 फीसदी के नीचे थी। आज 35 फीसदी से अधिक महिलाएं प्रदेश में सुरक्षा का माहौल होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। सीएम ने कहा कि यूपी में हेल्पलाइन 112 के माध्यम से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सर्विस और साइबर हेल्प लाइन को इंटीग्रेटेड करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। इससे एक सामान्य नागरिक न्याय प्राप्त कर कसेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और जबावदेही न्याय प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उच्चीकृत आरएफएसएल के लोकार्पण समारोह को सांसद रविकिशन ने भी संबोधित किया। स्वागत संबोधन में एडीजी तकनीकी सेवाएं नवीन अरोड़ा ने पुलिस महकमे में तकनीकी उन्नयन का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री को पुलिसिंग में नवोन्मेष का मार्गदर्शक बताया। आभार ज्ञापन डीआईजी तकनीकी सेवाएं आनंद कुलकर्णी ने किया। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता सहित प्रशासन एवं पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।

समस्याओं से निपटने का तरीका योगी सरकार से सीखें बाकी राज्य

इंद्रेश शर्मा

अपराधियों से निपटने और धार्मिक स्थलों की आड़ में आम लोगों का जीना दुश्वार करने वाले लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने की सीख उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी लेनी चाहिए। दलगत राजनीति से हटकर योगी सरकार ने साबित कर दिया है कि यदि इरादे मजबूत और व्यापक जनहित से जुड़े हों तो समझाइश से भी समस्या का हल किया जा सकता है। ऐसा धार्मिक स्थलों पर कानफाड़ू लाउडस्पीकर्स को हटा कर किया गया। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स की तेज आवाज से होने वाला ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। राजधानी लखनऊ में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर हटाने का अभियान के तहत वजीरगंज इलाके में पुलिस की टीम ने मस्जिदों और मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर और स्पीकर हटवाए।

पुलिसकर्मियों ने मस्जिदों के इमामों और मंदिरों पुजारियों को समझाया कि तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, इसे उतार लें। यह कार्रवाई धार्मिक नेताओं और स्थानीय समितियों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। उत्तर प्रदेश में 1400 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए या उनकी आवाज कम की गई। ये लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर लगे थे। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद की गई है। कानपुर जोन में इस अभियान के तहत 8 जिलों से 382 लाउडस्पीकर हटाए गए। मेरठ जोन में 381 लाउडस्पीकर हटाए गए। इनमें से अकेले हापुड़ से 110 लाउडस्पीकर निकाले गए, जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं। प्रयागराज जोन में, जहाँ 7 जिले शामिल हैं, 233 लाउडस्पीकर तय शोर सीमा से ज्यादा पाए गए। उन्हें आवाज को तय सीमा तक कम करने का निर्देश दिया गया, जबकि 51 लाउडस्पीकर हटा दिए गए। इस जोन में करीब 1200 लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। लखनऊ जोन में भी कम से कम 350 लाउडस्पीकर हटाए गए। आगरा जोन में भी करीब 150 लाउडस्पीकर हटाए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ध्वनि प्रदूषण से आम जनता को परेशानी न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नियमों के दायरे में ही होना चाहिए, ताकि किसी को असुविधा न हो। गौरतलब है कि योगी सरकार ने 2022 से यूपी के धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का अभियान शुरू किया था और अब तक यूपी में धार्मिक स्थलों से एक लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स हटाये जा चुके हैं वहीं, डेढ़ लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज कम की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थल के भीतर तक ही सीमित होने चाहिए।

सड़क पर किसी भी पर्व त्यौहार का आयोजन नहीं होना चाहिए, वहीं लाउडस्पीकर दोबारा न लगे यह जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन धार्मिक स्थल के परिसर में ही होना चाहिए। रास्तों में इसका आयोजन नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर हो रहे अजान को लेकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र

सरकार को चेतावनी दी थी। इसके बाद से ही देश के कई राज्यों में लाउडस्पीकर के खिलाफ आवाज उठने लगी। शहरी ध्वनि प्रदूषण चुपचाप हमारे समय की सबसे उपेक्षित जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरा है। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ. पर्यावरणीय उदासीनता नहीं है। यह संवैधानिक उपेक्षा की सीमा पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शांत क्षेत्रों में सुरक्षित सीमा दिन में 50 डीबी (ए) और रात में 40 डीबी (ए) है। फिर भी, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में, संवेदनशील संस्थानों के पास रीडिंग अक्सर 65 डीबी (ए)-70 डीबी (ए) तक पहुँच जाती है। शहरी ध्वनि प्रदूषण और त्यौहारों का शोर सुनने की क्षमता के लिए खतरा बन रहा है। जब 'शांत क्षेत्र' शोर का केंद्र बन जाते हैं, तो यह राज्य की क्षमता और नागरिक सम्मान पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। साल 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि पर्यावरणीय व्यवधान - जिसमें अत्यधिक शोर भी शामिल है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण (वी) मामले में, न्यायालय ने माना कि अनियंत्रित शहरी शोर मानसिक स्वास्थ्य और नागरिक स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण से होने वाली मौतों का कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि इससे हुए इस्कीमिक हृदय रोग के कारण लगभग 12,000 मौतों और प्रति वर्ष 48,000 नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, तनाव, नींद की कमी और सुनने में समस्या जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से मौतों का कारण बन सकती हैं। पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाली अर्थ फाइवआर संस्था ने 2023 में भारत में ध्वनि प्रदूषण पर एक व्यापक सर्वेक्षण में बताया गया कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का शोर का स्तर 50 डीबी की सीमा से लगभग 50 प्रतिशत अधिक था। 80 डीबी वाली ध्वनि कानों पर अपना प्रतिकूल असर शुरू कर देती है। 120 डीबी की ध्वनि कान के पर्दों पर भीषण दर्द उत्पन्न कर देती है और यदि ध्वनि की तीव्रता 150 डीबी अथवा इससे अधिक हो जाए तो कान के पर्दे फट सकते हैं, जिससे व्यक्ति बहरा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि भारत में ध्वनि प्रदूषण की वजह से कम सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत 6.3 करोड़ की आबादी ऐसी है, जो सुनाई नहीं देने की समस्या से पीड़ित है। इतना ही नहीं यूनाइटेड नेशंस एनवाइयरमेंट प्रोग्राम की ओर से जारी कई गई वार्षिक 'फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत के मुरादाबाद शहर को विश्व का दूसरे नंबर का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से शारीरिक और मानसिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खासकर इन एक्टिविटीज से भारत के युवा अपनी श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता तेजी से खोते जा रहे हैं। यही हाल रहा, तो साल 2030 तक भारत में कम सुनने वालों की संख्या दोगुनी से ज्यादा यानी 13 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में 10 में से दो लोग ही इस समस्या का इलाज करवाते हैं और श्रवण यंत्र पहनते हैं। नॉर्थ अमेरिका ब्रीडिंग बर्ड सर्वे के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में गौरैयों की संख्या 82 प्रतिशत तक कम हो चुकी है। शहरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण गौरैयों के जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट है। विश्व के सभी देशों में पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए जीव-जंतु, पेड़-पौधें, जल और इंसानों आदि का एक संतुलित संख्या में होना बेहद जरूरी है। इन सभी के संतुलन से ही पृथ्वी पर जीवनचक्र बना रहता है लेकिन बढ़ते प्रदूषण से हम जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उन सभी में किसी न किसी प्रकार से प्रदूषण के कण हमारे अंदर तो आते ही हैं। इसके साथ ही पशु-पक्षियों का भी अस्तित्व संकट में है।

पक्षियों को जल और वायु प्रदूषण से तो खतरा है ही इसके साथ ध्वनि प्रदूषण से उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ रहा है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्निथोलॉजी के शोधार्थियों ने जेब्रा फिंच नाम के पक्षी पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुताबिक पक्षियों के प्रजनन की शक्ति घट रही है और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखा गया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि शोर की वजह से पक्षियों के गाने-चहचहाने पर भी फर्क पड़ता है। कंजर्वेशन फिजियोलॉजी नाम की पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित भी किया गया है।

भारत का कानूनी ढाँचा, कागजों पर तो मजबूत है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में बिखराव है। ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 को शहरी वास्तविकताओं के अनुरूप शायद ही कभी क्रियान्वित किया जाता है। नगर निकायों, यातायात पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के बीच समन्वय बहुत कम है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एक राष्ट्रीय ध्वनिक नीति की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे ढाँचे में सभी क्षेत्रों में अनुमेय डेसिबल स्तरों को परिभाषित किया जाना चाहिए, नियमित ऑडिट अनिवार्य किए जाने चाहिए और स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाया जाना चाहिए। अंतर-एजेंसी तालमेल के बिना, प्रवर्तन छिटपुट और प्रतीकात्मक ही रहेगा।

शहरी शोर के विरुद्ध लड़ाई केवल नियामक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। शहरों को ध्वनि-सहिष्णुता की साझा नैतिकता विकसित करनी होगी। जन अभियानों को नारों से आगे बढ़कर स्कूलों, चालक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सामुदायिक स्थलों में गहन शिक्षा तक पहुँचाना चाहिए। जब तक भारत शहरी शोर के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण नहीं अपनाता, तब तक उसके स्मार्ट शहर ध्वनि के स्तर पर रहने लायक नहीं रह पाएँगे।

लाल किला विस्फोट के बाद उठते गंभीर सवाल

दिल्ली-एनसीआर और पुलवामा में लगातार छापेमारी से अलफलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर आतंकी डॉ. उमर नबी दबाव में आ गया था। वह फरीदाबाद से जल्दबाजी में अधूरा तैयार आईईडी लेकर कार से निकला, जिससे धमाका हुआ। इसलिए धमाके का असर सीमित रहा और क्रेटर या छर्रे नहीं मिले।

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भयानक धमाके ने न केवल देश की राजधानी दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया। शाम के करीब सात बजे जब दिल्ली अपनी सामान्य चहल-पहल में डूबी थी, अचानक लाल किला मैट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक तेज धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। कुछ ही पलों में कार जलते मलबे में बदल गई, आसपास खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई और घना धुआं आसमान में छा गया। यह दृश्य

चरण सिंह

किसी युद्ध के बाद की तबाही जैसा था, आवाज इतनी भयावह कि चांदनी चौक से लेकर जामा मस्जिद तक सायरन और चीखों की गूंज फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक सफेद हुंडई आई-20 कार में अचानक जबरदस्त विस्फोट हुआ। कार के परखच्चे उड़ गए और आग ने पास खड़ी गाड़ियों, ई-रिक्शा आदि को अपनी लपटों में ले लिया। कुछ ही सैकेंडों में पूरा इलाका दहशत के घेरे में था। विस्फोट की तीव्रता ने न केवल वाहनों को चूर-चूर किया बल्कि लाल किला और आसपास की इमारतों तक को हिला दिया, आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए और लोगों के दिलों में एक बार फिर वही पुराना भय लौट आया, वह भय जो दिल्ली ने 2001, 2005, 2008 और 2011 के धमाकों के दौरान महसूस किया था। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 12

लोगों की मौत हुई है जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आनन-फानन में जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई कि वाहन में कौन सवार था और विस्फोट से पहले क्या गतिविधियां हुई। जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं।

दिल्ली-एनसीआर और पुलवामा में लगातार छापेमारी से अलफलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर आतंकी डॉ. उमर नबी दबाव में आ गया था। वह फरीदाबाद से जल्दबाजी में अधूरा तैयार आईईडी लेकर कार से निकला, जिससे धमाका हुआ। इसलिए धमाके का असर सीमित रहा और क्रेटर या छर्रे नहीं मिले। धमाके वाले दिन, आई20 कार लाल किला पहुंचने से पहले दिल्ली के कई इलाकों से गुजरी थी। कार दोपहर ढ़ाई बजे कनॉट प्लेस पहुंची और कुछ देर बाद वहां से निकल गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार में विस्फोट सामाग्री वही थी, जो फरीदाबाद से जब्त की गई है। यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा है, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और यूपी में सक्रिय है। इस मामले में गिरफ्तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉ. शाहीन शाहिद ने स्वीकार किया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देशभर में हमलों की साजिश रच रही थी। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह पिछले दो सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी।

लाल किला केवल एक राष्ट्रीय स्मारक नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र और अस्मिता का प्रतीक है। इसकी दीवारों पर हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण गूंजता है। ऐसे पवित्र स्थल के समीप हुआ यह धमाका सुरक्षा व्यवस्था के सबसे गहरे स्तरों तक प्रश्न खड़े करता है। सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद राजधानी के दिल में यह घटना कैसे घट गई? दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की निगरानी में लाल किला सबसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, जहां नियमित रूप से सीसीटीवी, ड्रोन और बीट पैट्रोलिंग की जाती है। फिर भी यदि इस स्तर का विस्फोट हो सकता है तो यह केवल तकनीकी विफलता नहीं बल्कि सुरक्षा मानसिकता की जड़ता का भी संकेत है। यह दशार्ता है कि हम अब भी उस सुरक्षित भ्रम में जी रहे हैं, जहां खतरे को हमेशा दूर मान लिया जाता है, जब तक कि वह हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। इस धमाके की भयावहता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी और आसपास के वाहनों में आग फैल गई, फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया।

दिल्ली में ऐसा धमाका करीब 13 वर्षों बाद हुआ है। फरवरी 2012 में इजराइली राजनयिकों को निशाना बनाकर हुए बम धमाके के बाद से राजधानी अपेक्षाकृत शांत रही थी। उससे पहले 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट गेट नंबर-5 के पास हुए धमाके में 15 लोग मारे गए थे। 2008 के सिलसिलेवार धमाकों में तो दिल्ली का दिल ही दहल गया था, जब करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों में मौत और तबाही की कहानियां लिखी गई थी। उससे पहले 29 अक्तूबर 2005 को दीवाली से दो दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पहाड़गंज, गोविंदपुरी और सरोजिनी नगर में एक साथ तीन धमाके किए थे, जिनमें 60 से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। यह लंबा इतिहास बताता है कि दिल्ली हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है क्योंकि यह न केवल सत्ता का केंद्र है बल्कि देश की आत्मा है।

लाल किले के पास हुआ यह विस्फोट उस समय हुआ, जब फरीदाबाद में करीब तीन हजार किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ था। एक

कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान से 360 किलो विस्फोटक, हथियार और टाइमिंग डिवाइस बरामद किए गए थे। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें मेडिकल प्रोफैशनल्स और मौलवी भी शामिल बताए गए। इन दोनों घटनाओं के बीच कड़ियां जुडने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कोई गहरी साजिश पनप रही थी, जिसे शायद पूरी तरह रोका नहीं जा सका। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या हमारी खुफिया प्रणाली में समय रहते चेतावनी देने की क्षमता घट रही है? क्या सूचनाओं का साझा तंत्र अब भी कागजी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है? सुरक्षा केवल हथियारों, बुलेटप्रूफ जैकेटों या बड़ी टीमों से नहीं आती, यह निरंतर सतर्कता, सामुदायिक सहयोग और त्वरित इंटेलिजेंस साझा करने से बनती है। यदि फरीदाबाद जैसी घटनाओं के बाद तत्काल सतर्कता बढ़ाई जाती और वाहन जांच प्रणाली में रैंडम सर्च बढ़ाई जाती तो शायद यह विस्फोट टल सकता था।

बहरहाल, पीड़ितों के परिवारों के लिए यह दर्द केवल आंकड़ों का मामला नहीं बल्कि उनके लिए यह जीवन के उजाले का बुझ जाना है। अस्पतालों में घायल तड़प रहे हैं, कुछ ने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। प्रशासन के लिए यह करुणा और जिम्मेदारी की सबसे कठिन परीक्षा है। सरकार को त्वरित राहत, मुआवजा और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी होगी। अपराधियों को पकड़ने और दोषियों को सजा दिलाने में किसी भी तरह की देरी इस देश की न्यायिक साख पर सवाल उठाएगी। हमारी प्राथमिकता इस समय तीन दिशाओं में होनी चाहिए, पीड़ितों के प्रति संवेदना, जांच में निष्पक्षता और भविष्य के लिए सबक। लाल किले के पास हुआ यह धमाका चेतावनी है कि सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसे हर नागरिक की जागरूकता, तकनीकी सशक्तता और प्रशासनिक दृढ़ता के साथ ही साकार किया जा सकता है। यह समय दोषारोपण का नहीं बल्कि आत्ममंथन का है, यह सोचने का कि क्या हम सुरक्षा के हर स्तर पर सचमुच उतने सजग हैं, जितना एक जिम्मेदार राष्ट्र को होना चाहिए। दिल्ली की हवा में आज केवल धुआं नहीं बल्कि चिंता और सवाल तैर रहे हैं और जब तक इन सवालों का जवाब तथ्यों, साक्ष्यों और न्याय की कसौटी पर नहीं मिलता, तब तक यह विस्फोट केवल एक हादसा नहीं रहेगा बल्कि हमारी सामूहिक चेतना पर लगी गहरी चोट की तरह याद किया जाएगा। देश उम्मीद कर रहा है कि जांच एजेंसियां सच्चाई को उजागर करते हुए दोषियों को बेनकाब करेंगी और दिल्ली फिर से वही शहर बनेगी, जो हर संकट के बाद और मजबूत होकर उठ खड़ी होती है।

दिल्ली में कब-कब हुए धमाके

- 25 मई 1996 : लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में बम विस्फोटझ 16 लोगों की मौत.
- 1 अक्टूबर 1997 : सदर बाजार के पास 2 बम विस्फोट- 30 घायल.
- 10 अक्टूबर 1997 : शांतिवन, कौड़िया पुल एवं किंग्सवे कैंप इलाकों में तीन विस्फोट- एक की मौत, 16 घायल.
- 18 अक्टूबर 1997 : रानी बाग मार्केट में डबल विस्फोट- एक की मौत, 23 घायल.
- 26 अक्टूबर 1997 : करोल बाग मार्केट में 2 विस्फोट- 1 की मौत, 34 घायल.
- 30 नवंबर 1997 : रेड फोर्ट क्षेत्र में डबल विस्फोट- 3 की मौत, 70 घायल.
- 30 दिसंबर 1997 : पंजाबी बाग के पास बस में विस्फोट- 4 मरे, 30 घायल.
- 18 जून 2000 : रेड फोर्ट के निकट 2 विस्फोट- 2 की मौत, दर्जनभर घायल.
- 16 मार्च 2000 : सदर बाजार में विस्फोट- 7 घायल.
- 27 फरवरी 2000 : पहाड़गंज में विस्फोट- 8 घायल.
- 14 अप्रैल 2006 : जामा मस्जिद में 2 विस्फोट- 14 घायल.
- 22 मई 2005 : लिबर्टी एवं सत्यं सिनेमा हॉल में 2 विस्फोट- 1 की मौत, 60 घायल.
- 29 अक्तूबर 2005 : सरोजिनी नगर, पहाड़गंज व गोविंदपुरी में 2 विस्फोट- करीब 59-62 मरे, 100+घायल.
- 13 सितंबर 2008 : करोल बाग (गफ्फार मार्केट), कनॉट प्लेस व ग्रेटर कैलाश-कमें पांच विस्फोट- 20-30 मरे, 90+ घायल.
- 27 सितंबर 2008 : महरौली के फ्लावर मार्केट (सराय) में विस्फोट- 3 की मौत, 23 घायल.
- 25 मई 2011 : दिल्ली हाई कोर्ट पार्किंग में विस्फोट- कोई मौत नहीं.

दिल्ली बम धमाका: रक्षक बने भक्षक

हरेन्द्र शर्मा

व्यक्तियों की सोच दृष्टि और दृष्टिकोण किसी भी समाज को उच्च पद प्रतिष्ठा पर ले जा सकती है तथा उसे गिरा भी सकती है। व्यक्ति की कार्यशैली ही उसके व्यक्तित्व को महान और नीचता दोनों दिला सकती है। आज किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं? यह एक बड़ा प्रश्न समाज के सामने खड़ा हो रहा है। कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बात ठीक भी है। किसी भी समाज में गलत कार्य करने वाले गिने-चुने ही लोग होते हैं। लेकिन वह अपनी पूरे समाज, धर्म, जाति आदि व्यवस्था को बदनाम अर्थात भंग कर देते हैं। यही कुबुद्धि के लोग समाज के साथ राष्ट्र के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं और दिल्ली धमाके में ऐसा हुआ भी है।

अब प्रश्न यह भी है और लोग कहते भी हैं कि कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग ही दृष्टि भ्रमित होते या पथ भ्रमित होते हैं। वह कुछ भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। फिर विचार यह फैला कि धन अर्थात पैसे के अभाव में लोग पथ भ्रमित काम करते हैं और वह जुर्म या कोई भी देश विरोधी काम कर सकते हैं। इन उल्टे कामों से उसे धन मिलेगा, कुछ हद तक दोनों ही तथ्य सही भी हैं और ऐसा देखा भी गया है। लेकिन जैसे-जैसे युग बदला देश विरोधी ताकतों ने पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया। देश विरोधी किसी हद तक सफल भी हो रही है। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके में एक डॉक्टर ने विस्फोटक से भारी कार से 10 से अधिक लोगों की जान ले ली, दर्जनों भर से ज्यादा घायल हो गए। कितनी ही गाड़ियां जलकर राख हो गई, कितना ही आर्थिक नुकसान हुआ है।

डॉक्टर बनकर जो व्यक्ति देश विरोधी कामों में, देश को दहलाने, आतंकी घटनाओं में शामिल हो रहा है, यह कितनी ही घातक बात है। एक तरफ तो देश के युवाओं को डॉक्टरी जैसे पेपर अर्थात नीट में पास होने के लिए दिन-रात एक करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से मेडिकल की महंगी पढ़ाई सरकारी खर्चे पर पास करके दिल्ली धमाके को अंजाम देना, सरकार के लिए गहन चिंतन की बात है। सरकार तो हर वर्ग को मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन देश विरोधी ताकतें अपने मकसद में सफल हो जाती हैं और उसका अंजाम हुआ दिल्ली में धमाका।

देश में सभी सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, देश के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। शिक्षा और मेडिकल का क्षेत्र देश दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। एक अपने ज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान से देश दुनिया को सही रास्ते पर चलने का संदेश देता है, तो दूसरा सेवा भाव और व्यक्ति के शरीर में आए रोगों को दूर कर नया जीवन देने का कार्य करता है। लेकिन बहुत से शिक्षण संस्थान अपनी विचारधारा के चलते राजनीति का गढ़ बन गए हैं। देश विरोधी नारे वहां लगाए जाते हैं। देश के टुकड़े-टुकड़े करने की बात होती है। शिक्षक विद्यार्थी एक सुर में बोलते हैं। ऐसे आस्तीन के साँप समाज, देश दुनिया के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ऐसा कितनी ही बार देखा भी गया है।

देश में आतंकी हमले का एक बड़ा कारण यह भी है कि देश विरोधी ताकतों के साथ विदेशी ताकतें हमारे देश के तेजी से होते विकास को देखकर खुश नहीं है। वह किसी भी तरीके से देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। राजनीतिक उलट फेर कर अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं। देश को आर्थिक रूप से कमजोर चाहते हैं। स्थिर राजनीति को हटाकर अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। लोगों में अविश्वास दिखाना चाहते हैं। किसी भी देश के विकास का पहिया उसकी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से आगे बढ़ता है। वर्तमान में तेजी से बढ़ते देश को विदेशी ताकतें और देश विरोधी ताकतें दोनों मिलकर लोगों में अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। विदेशी ताकतें समझती हैं कि देश के लोग राजनीति, हमलों, आपसी झगड़ों में उलझे रहे और हम अपना काम निकाल लें। जब भी देश शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, तो आतंकवाद का दानव बोतल से बाहर निकाल दिया जाता है और विदेशी ताकत इसमें किसी हद तक सफल भी हो जाती हैं इसमें हमारे देश के भी कुछ लोग मिल जाते हैं और देश पर हमला कर दिया जाता है। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, बात की तहत तक जाकर उचित काम करना ही समझदारी की बात है।

चुनाव आयोग पर हमलावर राहुल पर भड़के बुद्धिजीवियों की नसीहत

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को 'चोर' कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद देश की लगभग 250 जानी-मानी हस्तियों ने उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इन हस्तियों में करीब सवा सौ पूर्व नौकरशाह, कुछ पूर्व जज, पूर्व सैन्य अफसर, शिक्षाविद, कलाकार और वरिष्ठ वकील शामिल हैं।

देश के राजनीतिक माहौल में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान ने नई विवाद की लपटें उठा दी हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को 'चोर' कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद देश की लगभग 250 जानी-मानी हस्तियों ने उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इन हस्तियों में करीब सवा सौ पूर्व नौकरशाह, कुछ पूर्व जज, पूर्व सैन्य अफसर, शिक्षाविद, कलाकार और वरिष्ठ वकील शामिल हैं।

इन सभी ने संयुक्त रूप से एक पत्र जारी कर राहुल गांधी के बयान को 'लोकतांत्रिक संस्थाओं पर असंवैधानिक हमला' करार दिया है। उनका कहना है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना हर नागरिक का दायित्व है, चाहे वह आम आदमी हो या किसी बड़े राजनीतिक दल का शीर्ष नेता। पत्र में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी जैसे स्थापित नेता जब सार्वजनिक मंचों से इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, तो इससे देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचता है और जनता के विश्वास को ठेस लगती है।

पूर्व नौकरशाहों और बुद्धिजीवियों के समूह ने यह भी कहा है कि विपक्ष का काम सवाल करना जरूर है, लेकिन वह आलोचना सभ्य संवाद की सीमा में रहकर होनी चाहिए। पत्र में लिखा गया है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल चुनाव आयोग की साख को धूमिल करता है, बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया में अविश्वास का माहौल भी पैदा करता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए घातक है। कांग्रेस नेता ने हाल ही में एक जनसभा के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि आयोग सत्तारूढ़ दल के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया कि आयोग का व्यवहार निष्पक्षता की सीमाओं से बाहर जा चुका

है और विपक्षी दलों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया। सत्तापक्ष के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की मूल संस्थाओं का अपमान बताया। वहीं विपक्ष ने राहुल के बचाव में कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठाना नागरिक अधिकार है।

हालांकि, जिन बुद्धिजीवियों ने यह विरोध पत्र लिखा है, उनका मानना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी 'लोकतंत्र के बुनियादी आदर्शों के विपरीत' है। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में संस्थाएं किसी राजनीतिक लाभ या हानि से ऊपर होती हैं और उन पर इस प्रकार के आरोप लगाना जनता को भ्रमित करता है। एक पूर्व कैबिनेट सचिव ने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब चुनाव निकट हों। इन हस्तियों में से कई ने पहले भी संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की वकालत की है। कुछ पूर्व जजों का कहना है कि चुनाव आयोग ने अब तक देश में कई कठिन परिस्थितियों में भी निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, और इस संस्था पर सवाल उठाना बिना ठोस सबूत लोकतंत्र को कमजोर करने के बराबर है। वहीं, कुछ पूर्व राजनयिकों का मानना है कि जब सार्वजनिक जीवन के बड़े नेता ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को भी क्षति पहुंचती है। इन हस्तियों ने अपने पत्र में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए 'संविधान बचाओ, संस्थाएं बचाओ' (एसआईआर) अभियान पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह अभियान एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पर सामूहिक अविश्वास जताने जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी संस्था से असहमति है तो उसके खिलाफ सबूतों के साथ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों से संस्थाओं को 'जनता का दुश्मन' बताने का अभियान चलाया जाए। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आज जब भारत विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब नेताओं को जनता में भरोसा और एकता का संदेश देना चाहिए, न कि उन्हें संस्थाओं के खिलाफ भड़काना चाहिए। समूह ने यह अपील की है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का सम्मान करें और उन्हें राजनीतिक विवादों से दूर रखें, ताकि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो सकें।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस कभी संस्थाओं के खिलाफ नहीं रही है, बल्कि उसने हमेशा उनकी जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का बयान सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव आयोग को अपने हित में उपयोग करने के संकेतों पर आधारित था, जो लोकतंत्र की सेहत के लिए खतरनाक है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब संस्थाएं सरकार के दबाव में काम करती दिखती हैं, तो जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए प्रश्न पूछना भी लोकतांत्रिक कर्तव्य है। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया है क्या संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना लोकतंत्र की सेहत के लिए आवश्यक है या यह उसकी जड़ों को कमजोर करती है? कई विशेषज्ञ इसे 'दो धार वाली तलवार' मानते हैं। उनके अनुसार, लोकतंत्र में संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठाना जरुरी है, लेकिन उसे व्यक्तिगत या अपमानजनक शब्दों में रूपांतरित करना अनुचित है।

पत्र जारी करने वाले समूह ने अंत में यह अपील भी की है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों को शब्दों की मयार्दा का ध्यान रखना चाहिए। जब देश के नेता या बड़े राजनीतिक चेहरे खुले मंच से संज्ञात्मक हमले करते हैं, तो समाज में नकारात्मकता फैलती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भाषणों से नहीं, बल्कि संस्थाओं के प्रति विश्वास और सम्मान से मजबूत होता है। अब यह विवाद किस दिशा में बढ़ेगा, यह आने वाले समय में ही तय होगा। लेकिन यह साफ है कि राहुल गांधी के बयान ने राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दे दी है जहां एक तरफ संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और गरिमा पर बहस तेज है, वहीं दूसरी ओर सत्तापक्ष और विपक्ष अपने-अपने दृष्टिकोण से लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह जरूर दिखा दिया है कि भारत के लोकतंत्र में बहस और मतभेद की परंपरा जिंदा है, लेकिन उसे संयम और जिम्मेदारी के दायरे में रखना ही समाज के हित में है।

यूपी में जातीय रैलियों पर रोक से संगठित होता हिन्दुत्व

बिहार से जो संदेश निकला है, उसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। वैसे भी यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में जातीय आधार पर होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक दृश्य में एक बड़ा बदलाव ला दिया है।

देश में क्या विभाजनकारी राजनीति करने वाले नेताओं का अंत का समय करीब आ गया है।

बिहार के नतीजों ने क्या बांटने और राज करने की राजनीति करने वाले नेताओं को सबक सिखा दिया है कि उन्हें अपनी भविष्य की राजनीति में बदलाव करना होगा। बिहार से जो संदेश निकला है, उसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। वैसे भी यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में जातीय आधार पर होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक दृश्य में एक बड़ा

कपिल शर्मा

बदलाव ला दिया है। इस फैसले का भी सीधा असर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों पर पड़ा है, जो लंबे समय से जाति आधारित राजनीति को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाए हुए हैं। योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ राज्य की राजनीतिक संस्कृति को बदलने की कोशिश है, बल्कि यह बीजेपी के लिए एक रणनीतिक फायदा भी बन सकता है। जातीय रैलियों पर रोक लगाकर योगी सरकार उन नेताओं और दलों के मंसूबे चकनाचूर करना चाहती है, जो हिंदू समाज को जाति और उपजाति के आधार पर बांटने की सियासत में लगे रहते हैं। इस फैसले के पीछे यह विश्वास है कि जातीय रैलियां समाज में विभाजन और तनाव पैदा करती हैं, जिससे राज्य की शांति और सद्भावना को खतरा होता है।

योगी सरकार का तर्क है कि राजनीति को जाति

बीजेपी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर योगी सरकार ने बीजेपी की इस रणनीति को और मजबूत किया है। अब जाति आधारित रैलियों के बिना अखिलेश यादव और मायावती के लिए अपने वोट बैंक को जोड़ना मुश्किल होगा...

और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समानता के आधार पर होना चाहिए। इस निर्णय से अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रणनीति जाति आधारित वोट बैंक को जोड़ने पर टिकी हुई है। अब उन्हें नए तरीके से जनता को संबोधित करना होगा, जिसमें जाति की बजाय विकास और समानता के मुद्दे आगे आएंगे।यह फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा भी है। बीजेपी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर योगी सरकार ने बीजेपी की इस रणनीति को और मजबूत किया है। अब जाति आधारित रैलियों के बिना अखिलेश यादव और मायावती के लिए अपने वोट बैंक को जोड़ना मुश्किल होगा, जबकि बीजेपी के लिए यह एक अवसर है कि वह हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर सके। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक का विस्तार हो सकता है।

गौरतलब है, बिहार के चुनावों में भी इसी तरह की राजनीतिक दिशा देखने को मिली है। बिहार में हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में मतदान किया। इस एकजुटता का असर यह हुआ कि जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों को बड़ा झटका लगा। बिहार के चुनाव ने यह संकेत दिया कि अब हिंदू समाज जाति और उपजाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर वोट देने लगा है। यह रुझान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, खासकर जब जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लग चुका है।योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यह संदेश है कि अब जाति और उपजाति के आधार पर विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार चाहती है कि राजनीति विकास, सुरक्षा और समानता के मुद्दों पर आधारित हो। इससे न सिर्फ राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, बल्कि जनता को भी अपने वोट के आधार को बदलना होगा।

इस फैसले के बाद अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपने वोट बैंक को जाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और समानता के मुद्दों पर जोड़ें। इससे उन्हें नए तरीके से जनता को संबोधित करना होगा, जिसमें जाति की बजाय विकास और समानता के मुद्दे आगे आएंगे। इस तरह की रणनीति अपनाने से उन्हें बीजेपी के खिलाफ एक नई राजनीतिक दिशा देनी होगी।योगी सरकार का यह कदम बीजेपी के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा भी है। बीजेपी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर योगी सरकार ने बीजेपी की इस रणनीति को और मजबूत किया है। अब जाति आधारित रैलियों के बिना अखिलेश यादव और मायावती के लिए अपने वोट बैंक को जोड़ना मुश्किल होगा, जबकि बीजेपी के लिए यह एक अवसर है कि वह हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर सके। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक का विस्तार हो सकता है। बिहार के चुनावों में भी इसी तरह की राजनीतिक दिशा देखने को मिली है। बिहार में हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में मतदान किया। इस एकजुटता का असर यह हुआ कि जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों को बड़ा झटका लगा। बिहार के चुनाव ने यह संकेत दिया कि अब हिंदू समाज जाति और उपजाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर वोट देने लगा है। यह रुझान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, खासकर जब जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लग चुका है।योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यह संदेश है कि अब जाति और उपजाति के आधार पर विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार चाहती है कि राजनीति विकास, सुरक्षा और समानता के मुद्दों पर आधारित हो। इससे न सिर्फ राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, बल्कि जनता को भी अपने वोट के आधार को बदलना होगा।

भारत में चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे जीवंत उत्सव है। मतदान जनता को अपनी आवाज सुनाने और नीतिगत दिशा तय करने का अवसर प्रदान करता है। इस दौरान प्रशासन निष्पक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ करता है—मतदान केंद्रों की तैयारी से लेकर जागरूकता अभियानों तक। चुनाव आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाएँ नागरिकों के भरोसे को मजबूत करती हैं। वोट देना केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जो राष्ट्र के भविष्य को दिशा देती है।

ब्रिज पंवार

लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुचिता का प्रश्न और एसआईआर की अनिवार्यता

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ शासन की असली शक्ति जनता के हाथों में निहित मानी जाती है। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संविधान की स्पष्ट व्यवस्था के अनुसार यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की निष्पक्ष संरचना और उसकी कार्यशैली द्वारा संचालित होती है। मतदाता सूची इस पूरी प्रक्रिया की आधारशिला है—क्योंकि उसी के माध्यम से नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

इसलिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता और शुचिता लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही संदर्भ विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया—स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है। मतदाता सूची में त्रुटियाँ कई रूपों में सामने आती हैं—मृत व्यक्तियों के नाम, एक व्यक्ति का दो स्थानों पर नाम, पात्र मतदाताओं के नाम का गायब होना, या पते के परिवर्तन के बावजूद संशोधन न होना। ऐसी स्थिति चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार देता है, जिसमें चुनाव संचालन, नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण शामिल हैं। अतः एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से स्थापित लोकतांत्रिक दायित्व है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही चुनाव आयोग नियमित रूप से मतदाता सूची में संशोधन करता रहा है। कुछ राज्यों में एसआईआर के दौरान बड़ी मात्रा में मृतकों के नाम हटाए गए, गलत प्रविष्टियाँ सुधारी गईं, और स्थानांतरित या नए पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। बिहार और बंगाल में हुए पुनरीक्षणों के उदाहरण बताते हैं कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े नामों को हटाने से मतदाता सूची अधिक वास्तविक और पारदर्शी बन सकी। बंगाल में 7.6 करोड़ मतदाताओं की सूची में से लगभग 47 लाख नाम हटाए गए, जिससे पता चलता है कि अगर

नियमित संशोधन न हो तो सूची कितनी विकृत हो सकती है।

मतदाता सूची में त्रुटियाँ केवल तकनीकी समस्या नहीं–वे चुनावी निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व के अधिकार और जनविश्वास पर सीधा आघात करती हैं। यदि किसी नागरिक का नाम सूची से गायब है, तो वह अपने मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार–मताधिकार–से वंचित हो जाता है। दूसरी ओर, मृतकों या स्थानांतरित लोगों के नाम बने रहने से फर्जी मतदान या राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है। इन विसंगतियों से लोकतंत्र की वैधता कमजोर होती है।

कुछ लोग एसआईआर को राजनीतिक हस्तक्षेप या सरकार द्वारा मतदाता सूचियों में हस्तक्षेप के रूप में देखने लगते हैं, जबकि यह शंका तथ्यहीन है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण किसी दल की जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग पूर्णतः स्वायत्त संस्था है और उसके निर्णय न्यायालयों द्वारा भी संरक्षित माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट कहा है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके लिए मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

एसआईआर के दौरान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि लोग स्वयं अपनी प्रविष्टियों की जाँच न करें, त्रुटियाँ सम्बंधित बूथ लेवल अधिकारियों को न बताएं, और दस्तावेज उपलब्ध न कराएं तो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जिनके नाम गलत होने पर वे स्वयं सुधार के लिए आगे नहीं आते। यह उदासीनता लोकतंत्र को कमजोर करती है। इसलिए चुनाव आयोग ने डिजिटल साधनों–जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑनलाइन फॉर्म, पोर्टल–का उपयोग बढ़ाया है ताकि लोग आसानी से संशोधन कर सकें।

एसआईआर के विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने, फर्जी मतदान रोकने और सही मतदाता आधार सुरक्षित करने के लिए है। जिन राज्यों में यह प्रक्रिया रोकी गई या राजनीतिक विवाद के कारण ठप हो गई, वहां मतदाता सूची में भारी त्रुटियाँ पाई गईं। ऐसे मामलों में न्यायालयों ने स्वयं दिशा-निर्देश जारी कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की आवश्यकता दोहराई है। अतः एसआईआर का विरोध लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध है।

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ 96 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, वहां मतदाता सूची का अद्यतन एक अत्यंत जटिल, विशाल और सतत प्रक्रिया है। इसे केवल सरकारी जिम्मेदारी मानना पर्याप्त नहीं; यह नागरिक कर्तव्य भी है। चुनाव आयोग केवल ढाँचा देता है, लेकिन उसे प्रभावी बनाने का दायित्व जनता के सहयोग पर निर्भर है। मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि को सही रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मतदान के दिन वोट देना।

अंततः, लोकतंत्र केवल मतदान का दिन नहीं–पूरी व्यवस्था का नाम है। इस व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मतदाता सूची की शुचिता सर्वोपरि है। एसआईआर यही सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हों।

यह लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा को जीवित रखता है और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। इसलिए मतदाता सूची के नियमित शुद्धिकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को भागीदारी के लिए प्रेरित करना और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को सहयोग देना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।

भारतीय जनता पार्टी यूपी-बंगाल में भी महिलाओं-युवाओं पर लगाएगी दांव

एनडीए की 202 सीटों वाली ऐतिहासिक जीत के पीछे आधी आबादी का हाथ साफ दिख रहा है। महिलाओं ने 71.78 प्रतिशत मतदान कर पुरुषों के 62.98 प्रतिशत को पीछे छोड़ दिया, और यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का आईना है।

प्रवीण सिंह कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ नीतीश कुमार को दसवीं बार मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा फॉर्मूला सौंप दिया जो अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में परखा जाएगा। एनडीए की 202 सीटों वाली ऐतिहासिक जीत के पीछे आधी आबादी का हाथ साफ दिख रहा है। महिलाओं ने 71.78 प्रतिशत मतदान कर पुरुषों के 62.98 प्रतिशत को पीछे छोड़ दिया, और यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का आईना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता इसे 'वाई' यानी वीमेन-यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स की जीत बता रहे हैं, जहां जातीय समीकरण टूटे और विकास की योजनाओं ने वोटों का ध्रुवीकरण किया। अब सवाल यह है कि क्या यह मॉडल यूपी की योगी सरकार और बंगाल की ममता बनर्जी की चुनौतियों को पार कर पाएगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हां, अगर बजट से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक सही दांव चले गए।बिहार की धरती पर जो कुछ हुआ, वह कोई संयोग नहीं था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 67.13 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 के बाद का रिकॉर्ड है। लेकिन असली खेल तो महिलाओं ने खेला। नीतीश सरकार की 'महिला स्वरोजगार योजना' के तहत डेढ़ करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये की किस्त पहुंची, और यह पैसा वोटिंग बूथों पर लंबी-लंबी कतारों के रूप में दिखा। एक तरफ लालू प्रसाद के पुराने मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण की बातें हवा में तैर रही थीं, वहीं आधी आबादी ने एनडीए को ऐसा साथ दिया कि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। भाजपा अकेले 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, और जनता दल यूनाइटेड को 85 मिलीं।

विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं ने न सिर्फ संख्या बल्कि गुणवत्ता में भी योगदान दिया। जहां पुरुष वोटरों में सत्ता-विरोधी लहर की चर्चा थी, वहां महिलाओं ने योजनाओं के ठोस असर को प्राथमिकता दी। उदाहरण के तौर पर, दरभंगा की अलीनगर सीट से भाजपा की 25 वर्षीय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने 11,730 वोटों से जीत हासिल की, जो युवा महिलाओं की नई ऊर्जा का प्रतीक बनीं। कुल 88 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें से 28 विजयी रहीं, और भाजपा ने 13 में से 10 को जीतकर रिकॉर्ड बनाया। यह जीत सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि एक नए वोट बैंक की स्थापना की है, जहां जाति से ऊपर उठकर विकास और सुरक्षा का मुद्दा हावी हो गया।अब नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार साढ़े आठ साल के शासन में कानून-व्यवस्था का पर्याय बन चुकी है। बिहार की सफलता से प्रेरित होकर

भाजपा यहां 'वाई' फॉमूर्ले को और मजबूत करने की तैयारी में है। फरवरी 2025 में पेश हुए 2025-26 के बजट को ही देख लीजिए 8,08,636 करोड़ रुपये का यह 'चुनावी बजट' महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जो बेरोजगार युवाओं को लोन और ट्रेनिंग का वादा करता है।इसी तरह, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना पर 2,980 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया, जिससे लाखों महिलाओं को मासिक सहायता मिलेगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना ने भी सुर्खियां बटोरीं, और लाड़ली बहना जैसी योजनाओं की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का रोडमैप तैयार हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले बजट में रोजगार पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।

योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन कर 60 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया, जो बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के हुआ। यह भरोसा अब विधानसभा चुनाव में कैशेबल हो सकता है।लेकिन यूपी की सियासत सिर्फ योजनाओं पर नहीं थमेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी 'पीडीए' यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स को मजबूत करने में जुटे हैं, जो लोकसभा 2024 में कामयाब रही थी। उपचुनावों में यह कमजोर पड़ी, लेकिन अखिलेश इसे आजमाने को तैयार हैं। भाजपा की काट के तौर पर 'वाई' समीकरण ही काम आएगा।बिहार में जहां एमवाई फॉमूर्ला टूटा, वहां यूपी में यादव वोटों का बिखराव भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एनडीए के यादव उम्मीदवारों ने बिहार में महागठबंधन से ज्यादा सीटें जीतीं, और यूपी में भी ऐसा ट्रेंड दिख सकता है। ऊपर से कानून-व्यवस्था का मुद्दा। योगी सरकार ने महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जहां एनकाउंटर और सख्त कार्रवाई ने महिलाओं में सुरक्षा की भावना जगाई। पिछले दो सालों में ऐसे सैकड़ों केसों में त्वरित न्याय हुआ, जो चुनावी साल में 'बेटी बचाओ, अपराधी ठोको' का नारा बन सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर बजट में महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये वाली स्वरोजगार योजना जैसा कुछ आया, तो सपा का पीडीए समीकरण धराशायी हो

सकता है।

पश्चिम बंगाल की सियासत में तो यह फॉमूर्ला और भी रोमांचक साबित होगा। 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने बिहार मॉडल को ही आधार बनाया है। पार्टी का लक्ष्य 160 सीटें है, और हर बूथ पर नजर रखने के लिए 'चौकड़ी' तैयार की गई है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव, सह प्रभारी सुनील बंसल और आईटी हेड अमित मालवीय।बिहार जीत के ठीक बाद बंगाल में लड्डू बांटे गए, और पीएम मोदी ने इसे 'ममता मैजिक तोड़ने' का संकेत दिया। यहां बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा बनेगा। आरजी कर घोटाला, दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के गैंगरेप जैसे मामले तृणमूल कांग्रेस की कमजोरी उजागर कर रहे हैं। भाजपा व्यक्तिगत हमलों से बचते हुए मुद्दों पर फोकस करेगी, जैसा कि अक्टूबर 2025 में रणनीति बदली गई थी।

बंगाल भाजपा प्रमुख समिक भट्टाचार्य का दावा है कि 2026 में सत्ता उनके हाथ आएगी। युवाओं को साधने के लिए डिजिटल कैंपेन और बूथ मजबूती पर जोर होगा, जबकि महिलाओं के लिए बिहार जैसी योजनाओं का विस्तार। तीन साल से लगे तंबू अब फल ला रहे हैं, और बिहार का प्रयोग यहां अलग रंग में चलेगा जहां बंगाल की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाएगा।यह सब देखकर लगता है कि भाजपा ने बिहार से एक टेम्प्लेट तैयार कर लिया है, जो जाति की दीवारें तोड़कर विकास की नींव रखेगा। यूपी में जहां योगी का 'ठोक दो' मॉडल महिलाओं को आकर्षित कर रहा है, वहीं बंगाल में ममता की किलेबंदी को भेदने के लिए सामूहिक नेतृत्व और पीएम मोदी के विकास एजेंडे पर दांव लगेगा।लेकिन चुनौतियां कम नहीं। यूपी में सपा का पीडीए अभी भी मजबूत है, और बंगाल में तृणमूल का स्थानीय समर्थन। फिर भी, आंकड़े बोलते हैं बिहार में 71.78 प्रतिशत महिला वोटिंग ने खेल पलट दिया, और अगर यूपी-बंगाल में 60 प्रतिशत भी ऐसा हुआ, तो 2026 का नक्शा बदल जाएगा।राजनीति के इस नए दौर में 'वाई' ही राज करेगा, जहां आधी आबादी और युवा ऊर्जा मिलकर इतिहास रचेंगे। कुल मिलाकर, बिहार की लहर अब पूरे हिंदुस्तान को छू लेगी, और भाजपा का यह दांव या तो मास्टरस्ट्रोक साबित होगा या सबक। वक्त ही बताएगा, लेकिन तैयारी तो जोरों पर है।

रेल सुरक्षाः सुधार की पटरियों पर कब चढ़ेगा सिस्टम?

संजय बैंसला

भारत की रेल पटरियां देश की धमनियां कही जाती हैं, जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, जो अर्थव्यवस्था का इंजन चलाती हैं, जो इस विशाल देश की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं लेकिन जब इन्हीं पटरियों पर बार-बार मौत की चीखें गूंजती हैं तो सवाल केवल हादसों का नहीं रहता बल्कि उस पूरे तंत्र की आत्मा पर उठता है, जिसने सुरक्षा को केवल एक चुनावी 'घोषणापत्र' सरीखा बनाकर रख दिया है। बिलासपुर के लालखदान में हुआ हालिया रेल हादसा इसी गहरी लापरवाही का ताजा उदाहरण है, जहां एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 11 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए। इंजन मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया और वह मंजर किसी युद्धस्थल से कम नहीं था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह दुर्घटना देश के लिए महज एक और संख्या नहीं है बल्कि इस बात की प्रतीक है कि भारत के रेल तंत्र में तकनीक, सतर्कता और जवाबदेही का घोर अभाव है। बिलासपुर कलेक्टर के अनुसार, ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और गतौरा-बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि देश में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था आज भी 'कागज पर कवच' से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे की भयावहता के साथ ही जब हम इसी साल के कुछ अन्य रेल हादसों पर नजर डालते हैं, तो एक सिहरन सी उठती है।

महाराष्ट्र के ठाणे में जून 2025 में चार यात्रियों की मौत केवल इसलिए हुई थी क्योंकि भीड़भाड़ वाली दो लोकल ट्रेनों में पायदान पर लटकते यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए थे। बिहार के कटिहार में जून 2025 में अवध असम एक्सप्रेस रेलवे ट्रॉली से टकरा गई, जिससे एक ट्रॉलीमैन की मौत और चार कर्मचारी गंभीर घायल हुए। मार्च में ओडिशा के कटक जिले में बेंगलुरू-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अप्रैल 2025 में झारखंड के साहेबगंज में दो मालगाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई। जुलाई 2025 में उसी जिले के बरहड़वा में बिना लोको पायलट की 14 बोगियां तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी मालगाड़ी से जा टकराईं।

बिलासपुर का हादसा तो इस साल का सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बन चुका है। यह स्पष्ट संकेत है कि हादसे अब अपवाद नहीं बल्कि

एक भयानक पैटर्न बन चुके हैं। हर बार रेल मंत्रालय बयान देता है, 'दोषियों पर कार्रवाई होगी', 'मुआवजा दिया जाएगा', 'जांच समिति गठित की गई है', और फिर कुछ ही दिनों में सब भुला दिया जाता है। सवाल है कि क्या रेलवे अब केवल 'प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र' बन गया है, जहां कार्रवाई केवल तभी होती है, जब हादसा हो चुका होता है? भारत में रेल हादसों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी रेल सेवा स्वयं। भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में होने वाले रेल हादसों में से करीब 70 प्रतिशत हादसे मानव त्रुटि के कारण होते हैं यानी कि या तो सिग्नलिंग सिस्टम में गलती या ट्रैक निरीक्षण में लापरवाही या फिर ट्रेन संचालन में मानवीय भूल। शेष हादसे तकनीकी खराबी, पुरानी पटरियों, रखरखाव की कमी और ओवरलोडिंग के कारण होते हैं।

इन तथ्यों से यह साफ हो जाता है कि भारत की रेल प्रणाली में सुरक्षा संस्कृति का अभाव है। यहां तकनीक पर निवेश से अधिक जोर घोषणाओं पर है। बीते वर्षों से 'कवच' सिस्टम को लेकर खूब प्रचार किया गया, कहा गया कि यह एक ऐसा स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम है, जो दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगा लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश के केवल 4 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर ही कवच लागू हुआ है, बाकी 96 प्रतिशत ट्रैक आज भी मानव सतर्कता पर निर्भर हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। रेल प्रशासन का रवैया भी उतना ही असंवेदनशील है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी जाती है लेकिन यह मुआवजा न किसी बच्चे को उसका पिता लौटा सकता है, न किसी पत्नी को उसका पति, न किसी मां को उसका बेटा। जरूरत मुआवजे की नहीं, जवाबदेही की है।

यह दुर्भाग्य है कि जिस भारतीय रेलवे को 'विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था' कहा जाता है, वहां अब भी अधिकांश ट्रैक ब्रिटिश कालीन तकनीक पर चल रहे हैं। ट्रेन ड्राइवरों को 8 से 12 घंटे तक बिना विश्राम रेल चलाने की मजबूरी, सिग्नलिंग उपकरणों की खराबी और निरीक्षण प्रणाली की औपचारिकता, ये सब मिलकर दुर्घटना की जमीन तैयार करते हैं। ऐसी किसी भी घटनां के बाद हर बार राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, रेल मंत्री हादसे की उच्चस्तरीय जांच का ऐलान करते हैं और कुछ हफ्तों बाद कोई नई परियोजना या वंदे भारत उद्घाटन के बीच वह घटना जनता की स्मृति से

मिट जाती है लेकिन जो परिवार अपनों को खो चुके होते हैं, उनके लिए वह हादसा जीवनभर की सजा बन जाता है।

भारत में आज रेलवे की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा का वास्तविक आधुनिकीकरण। केवल कवच सिस्टम ही नहीं बल्कि ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे, स्वचालित सिग्नलिंग, लोको पायलट के थकान-निगरानी उपकरण और रीयल-टाइम संचार प्रणाली की अनिवार्यता। 2024 में रेलवे ने दावा किया था कि 2027 तक 50,000 किलोमीटर नेटवर्क कवच से लैस होगा लेकिन आज की प्रगति देखकर यह लक्ष्य किसी दिवास्वप्न जैसा लगता है। नवंबर 2024 तक कवच सिस्टम लगभग 1,548 किलोमीटर ट्रैक पर लागू हो चुका था और उसके बाद से धीमी गति से इसका विस्तार जारी है। ऐसे में 2027 तक 50,000 किलोमीटर कवच से लैस करने का लक्ष्य प्राप्त करना अभी बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है और लक्ष्य से काफी पीछे है। विस्तृत कवच नेटवर्क के लिए काफी संसाधन और समय की आवश्यकता है। सवाल यह भी है कि जब देश अंतरिक्ष में चंद्रयान उतार सकता है तो पटरियों पर सुरक्षित यात्रा क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकता? यह केवल तकनीक का नहीं, प्राथमिकता का प्रश्न है। जब तक सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखा जाएगा, जब तक रेल बजट में सुरक्षा खंड को लागत नहीं बल्कि निवेश नहीं माना जाएगा, तब तक यह रक्तरंजित यात्रा जारी रहेगी।

बहरहाल, अब समय आ गया है, जब रेल हादसों को मात्र दुर्घटनाएं कहकर टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये घटनाएं अब प्रशासनिक अपराधों का रूप ले चुकी हैं। हर साल निर्दोष नागरिकों की जानें जाती हैं और जिम्मेदारी जांच रिपोर्टों की धूल में दबी रह जाती है। देश को अब उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, जहां 'हादसे के बाद कार्रवाई' ही नीति बन चुकी है। आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था की, जो दुर्घटनाओं से पहले सतर्कता और रोकथाम सुनिश्चित करे। यात्रियों की सुरक्षा कोई दया नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है, जो केवल कागज पर नहीं, पटरियों पर भी सुरक्षित होना चाहिए। जब तक हर ट्रेन यात्रा भय से नहीं, विश्वास से शुरू और समाप्त नहीं होती, तब तक भारतीय रेल प्रगति की नहीं, असंवेदनशीलता की प्रतीक बनी रहेगी। सच्चा विकास तभी होगा, जब हर गंतव्य तक पहुंचने वाली ट्रेन हर यात्री को सुरक्षित जीवन की गारंटी दे सके।

70 साल में भी वेस्ट यूपी नही बनी हाईकोर्ट बेंच

1948 में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर था। वैसे 1955 की विधि आयोग की सिफारिशों ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी।

अजीत शर्मा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने की मांग एक बहुत पुराना और लगातार जारी रहने वाला आंदोलन है। लगभग 70 साल पुरानी यह मांग केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक गहरी पुकार है। इस आंदोलन के कामयाब न होने की खास बात यह है कि आंदोलनरत वकील आदोलन से जनता को नही जोड़ सके। वह यह बताने में और जनता में मन में बैठाने में असफल रहे कि हाईकार्ट की बैंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनने से यहां के रहने वालों को क्या लाभ होगा?

1948 में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर था। वैसे 1955 की विधि आयोग की सिफारिशों ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। आयोग ने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय की बेंच उन क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ से दूरी

अधिक है। साल 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की। वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने केंद्र को खंडपीठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भेजा। जनता पार्टी के शासन में राम नरेश यादव की सरकार ने भी इस मांग पर मुहर लगाई और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को कर उसे केंद्र सरकार को भेजा। बनारसीदास सरकार एवं बाद में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में भी एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को संस्तुति प्रदान की गईं। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया।

1970 और 1980 के दशक में, यह आंदोलन और भी जोर पकड़ने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव और अजित सिंह जैसे नेताओं ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया। इससे यह मांग राजनीतिक मुद्दा बन जरूर बन गई किंतु नेताओं की इच्छा शक्ति के अभाव में और इलाहाबाद के वकीलों के दबाव में कभी पूरी नही हुई। आज भी, पश्चिमी यूपी के कई संगठन और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर नियमित रूप से आंदोलन करते रहते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा से इलाहाबाद की दूरी 500 से 700 किलोमीटर है। इस लंबी दूरी के कारण मुवक्किलों और वकीलों को अत्यधिक समय, धन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। गरीबी और संसाधनों की कमी वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा बोझ बन जाता है। इलाहाबाद में एक मुकदमे के लिए जाने का मतलब है, न केवल यात्रा का खर्च, बल्कि वहाँ रहने और खाने का भी खर्च। इसके अलावा, वकीलों की फीस भी अधिक होती है। यह सब मिलकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय को बहुत महंगा बना देता है। एक बात और इलाहाबाद की जगह यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लखनऊ खंड पीठ से संबद्ध कर दिया जाता, तब भी दूरी दौ सौ किलोमीटर के आसपास कम हो जाती। लखनऊ पश्चिम उत्तर प्रदेश के नजदीक पड़ता है किंतु ऐसा भी नहीं किया गया।इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले से ही मुकदमों का भारी बोझ है। पश्चिमी यूपी से आने वाले मामलों की बड़ी संख्या के कारण, न्याय में और अधिक देरी होती है। एक बेंच की स्थापना से मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, जिससे न्यायपालिका पर दबाव कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अक्सर ₹भारत का चीनी का कटोरा₹ कहा जाता एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से इस क्षेत्र की न्यायिक और राजनीतिक पहचान मजबूत होगी, और यह एक आत्मनिर्भर केंद्र बन सकेगा।

वर्तमान में भी यह आंदोलन जारी है, हालाँकि इसने कई बार धीमी गति पकड़ी है। 1981 से वकीलों के संगठन नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को हड़ताल करते हैं, वे धरने देते रहतें हैं, और ज्ञापन सौंपते हैं। हालांकि, इस आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के सामने सबसे बडी चुनौती है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मांग को टालती रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील इस मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बेंच की स्थापना से उनका काम और आय प्रभावित होगी। सरकार का तर्क है कि एक बेंच की स्थापना से प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी और यह एक आर्थिक बोझ होगा। इसके अलावा, सरकार अक्सर इस मुद्दे को भविष्य के लिए टाल देती है। एक मजबूत और एकीकृत नेतृत्व की कमी ने इस आंदोलन को कमजोर किया है। अलग-अलग संगठन अपने-अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, जिससे एकता नहीं बन पाती।

हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापना के लिए सांसद अरुण गोविल मुखर हो गए हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग उठाने के बाद सांसद अब अधिवक्ताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कराएंगे। इसके लिए सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के लिए मिलने का समय मांगा है।

सांसद ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ आबादी को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय की चार बेंच हैं।मध्य प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़े होने के बाद भी यहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल है। सांसद ने कहा कि यहां बेंच मिलने से कम समय में न्याय मिलेगा और धन की भी बचत होगी।एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न केवल पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय तक पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि यह पूरे राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा। यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका और सभी हितधारक मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालें।

पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक नई पीठ ओर राज्य में चौथी हाईकोर्ट बेंच के गठन की अधिसूचना एक अगस्त को जैसे ही जारी हुई यूपी के मेरठ में सरगर्मियां बढ़ गईं। 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति' ने तुरंत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के बार अध्यक्षों और महामंत्री के साथ बैठक की. समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से सवाल किया कि जब कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की चौथी बेंच खुल सकती है तो यूपी के मेरठ में हाईकोर्ट की तीसरी बेंच क्यों नहीं स्थापित हो सकती? मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के वकीलों ने चार अगस्त को हड़ताल कर प्रदर्शन किया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना का आंदोलन पिछले लगभग 70 साल से जारी है। कब तक जारी रहेगा, यह भी नही कहा जा सकता।इतना जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 70 साल चलने वाला यह आंदोलन लंबी अवधि तक चलने वाले आंदोलनों में जरूर दर्ज हो गया है।

मिशन-2026: माओवादी आतंक का खात्मा तय

यानी संदेश साफ है कि नक्सलवाद-माओवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति तय है। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद-माओवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित है। ये अभियान अपने अंतिम चरण पर है।

सचिन तोमर

देश सहित छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। छत्तीसगढ़ का कुख्यात माओवादी आतंकी हिडमा 18 नवंबर को मारा गया। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने हिडमा की पत्नी समेत कुल 6 नक्सली-माओवादियों को ढेर कर दिया है।

वस्तुतः नक्सलवाद-माओवाद के समूलनाश के पीछे केन्द्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। जो सरेंडर करने वालों का स्वागत भी कर रही है। पुनर्वास भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अगर माओवादी, आतंक का रास्ता नहीं छोड़ते तो उनका अंत भी तय है। यानी मिशन-2026 पूरी तरह से एक्टिवेट है। 17 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यान

में भी माओवादी आतंक की समाप्ति का ज़िक्र किया। अर्बन नक्सलियों और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि-'पूरे देश में नक्सलवाद-माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था।

आप भी जानते हैं, बीते पांच दशकों तक देश का करीब-करीब हर बड़ा राज्य, माओवादी आतंक की चपेट में, चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती-पोसती रही और सिर्फ दूर-दराज के क्षेत्रों में जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद-पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी-बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया है।'

साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरी गंभीरता के साथ देश की एकता पर गंभीर खतरे को भी चिन्हांकित किया। उन्होंने कहा कि - '10-15

मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। जो सरेंडर करने वालों का स्वागत भी कर रही है। पुनर्वास भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अगर माओवादी, आतंक का रास्ता नहीं छोड़ते तो उनका अंत भी तय है।

साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली, माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, MMC बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, अपने स्वार्थ में देशहित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है।' यानी संदेश साफ है कि नक्सलवाद-माओवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति तय है। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद-माओवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित है। ये अभियान अपने अंतिम चरण पर है। साथ ही नक्सलवाद-माओवाद को पालने-पोसने वालों और समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है। अगर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से खेलेंगे तो अंजाम बुरा होगा।

वहीं छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजयशर्मा जिस तरह से नक्सलवाद-माओवाद के उन्मूलन में मिशन मोड में लगे हैं। वो काबिले तारीफ है। माओवादी हिडमा के मारे जाने के पहले विजय शर्मा उसके गांव पूवर्ती गए थे। हिडमा की मां के साथ भोजन किया था। पुत्रवत रुप में उनका आदर सत्कार किया था। हिडमा की मां से सरेंडर करवाने के लिए अपील भी करवाई थी। इसके बाद जब हिडमा ने सरेंडर नहीं किया तो सुरक्षाबलों ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया।

2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की वापसी होने के बाद बस्तर क्षेत्र से माओवादियों का खात्मा हो रहा है। व्यापक स्तर पर आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। पहले 'बोली' फिर 'गोली' दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। स्थायी शांति की ओर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया है चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। माओवादियों का 'अर्बन' मॉडल जिसे 'अर्बन नक्सली' के नाम से जाना जाता है। वो अभी भी देश भर में सक्रिय हैं। नई रणनीतियों पर लगा हुआ है। लेकिन ये तय है कि देश भर से नक्सलवाद-माओवादी आतंकवाद का खात्मा होगा। अर्बन नक्सलियों के ताबूत में भी अंतिम कील ठोंकी जाएगी। स्थायी शान्ति और विकास की बहाली होगी। ये नया भारत है। जो अपने नागरिकों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है देशविरोधी कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

बिहार में ऐतिहासिक जीत मोदी का कोई तोड़ नहीं

विपक्षी दलों को क्या लगता कि केवल आचार संहिता लगते ही चुनावी जंग जीती जाती है? अगर ये सोचते हैं तो इससे बड़ी भूल भला क्या हो सकती है? जनता हर समय राजनीतिक दलों, उनके नेताओं के आचरणों को देखती है। परखती है। उसके बाद धैर्यपूर्वक ढंग से आंकलन करती है। तत्पश्चात अपना निर्णय सुनाती है।

बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत

प्रतीकों, मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं की पिच पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे। ये मोदी और बीजेपी की पसंदीदा पिच है। अगर इस पर विपक्ष फंसा तो उसकी करारी हार सुनिश्चित है विपक्ष हर बार यही गलती करता है। वो भारतीय मानस को समझे बिना मोदी को ललकारता है। हिंदू संस्कृति के मानबिंदुओं, परंपराओं और आस्था पर कटाक्ष करता है। अपमानित करता है। विपक्ष को लगता है कि वो हिंदुत्व को गाली देकर जीत सकता है।

विपक्ष को लगता है कि वो भारतीय सेना के शौर्य को चुनौती देकर चुनाव जीत सकता है। विपक्ष को ये लगता है कि जाति के नाम पर विभाजन उत्पन्न कर जीत सकता है। अगर इस मुगालते में विपक्ष है तो वो मोदी से कभी नहीं जीत सकता है। क्योंकि कौन से प्रतीकों को कहां और किस अंदाज में आजमाना है। ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बखूबी जानते हैं। यूं कहूं तो वो इसमें सिद्धहस्त हैं। इसके जादूगर हैं।

हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा के ये परिणाम बता रहे हैं कि - आप हिंदू संस्कृति का अपमान कर कोई भी चुनावी किला फतह नहीं कर सकते। आप सांविधानिक संस्थाओं का अपमान कर चुनाव नहीं जीत सकते। विपक्ष को ये समझना होगा कि जिस Gen-Z के नाम पर देश में नेपाल जैसी अराजकता का बिगुल फूंका जा रहा था। भारत के Gen-Z ने उसकी हवा निकाल दी है। उसने भर-भर के एकमुश्त वोट NDA की झोली में डालकर राजतिलक कर दिया है। महिलाओं ने बड़ी खामोशी से प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास जताया है।

देश की जनता ये जान चुकी है कि वर्षों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल अब मुद्दाविहीन हो चुके हैं। क्या देश की जनता को ये नहीं दिखता रहा है कि - कैसे समूचा विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे

देश की जनता ये जान चुकी है कि वर्षों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल अब मुद्दाविहीन हो चुके हैं। क्या देश की जनता को ये नहीं दिखता रहा है कि - कैसे समूचा विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा था।

रहा था। क्या देश की जनता ये नहीं देख रही थी कि- कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन अराजकता का वातावरण बना रहा था। राष्ट्रीय हित के मुद्दों में इंडी गठबंधन के दलों का गतिरोध, तुष्टिकरण क्या देश की जनता नहीं देख रही थी?

विपक्षी दलों को क्या लगता कि केवल आचार संहिता लगते ही चुनावी जंग जीती जाती है? अगर ये सोचते हैं तो इससे बड़ी भूल भला क्या हो सकती है? जनता हर समय राजनीतिक दलों, उनके नेताओं के आचरणों को देखती है। परखती है। उसके बाद धैर्यपूर्वक ढंग से आंकलन करती है। तत्पश्चात अपना निर्णय सुनाती है।

जीत के ये आंकड़े बता रहे हैं कि –देश की जनता जान चुकी है कि विपक्ष ऐनकेन प्रकारेण केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनकी नीयत में खोट है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों को निगल जाने के बाद केवल 99 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस जिस ढंग से गैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। कांग्रेस के नेता और विशेष तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से मोदी विरोध में–देश विरोधी मानसिकता से ग्रस्त दिख रहे हैं। सामाजिक समरसता को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। देशद्रोही कम्युनिस्टों की लाइन पर चल रहे हैं। भारतीय समाज में अराजकता, हिंसा फैलाने जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कम्युनिस्टों ने राहुल गांधी को हाईजैक कर लिया हो। क्या जनता ये सब नहीं देखती है?

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से लेकर, हिंदुत्व, छठी मैया आदि के विरुद्ध राहुल गांधी के अनर्गल बयान। मिथ्याप्रचार। भारतीय सेना को अपमानित करते हुए विभाजनकारी बयान देना। बात-बात में हिंदुओं को जातियों में बांटने की वकालत करना। भाषा के आधार पर विभाजन के बीज बोना। तुष्टिकरण के लिए नए वक्फ कानून के विरोध में उतरना। घुसपैठ जैसी घातक समस्या को खारिज करना। लव जिहाद और कन्वर्जन के आतंक के विरुद्ध चुप्पी साधे रहना। मौन समर्थन देना। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को मजाक बना देना। विदेशों में जाकर भारत की सांविधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना। हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर आघात करना। कम्युनिस्टों की तर्ज. पर माओ की तरह रेड बुक रखना। बार-बार संविधान का माखौल उड़ाना। फर जैसे राष्ट्रनिष्ठ संगठनों पर झूठे आक्षेप लगाना। कांग्रेस शासित राज्यों में संविधान की हत्या करते हुए प्रतिबंध लगाने का कुकृत्य करना। प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठे ओबीसी वर्ग से आने वाले – नरेंद्र मोदी जी को – तू-तड़ाक जैसी भाषा से संबोधित करना। जनता ये सब देख रही थी और ये भी गांठ बांध रही थी कि – जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के प्रति ऐसी घृणा रखता है। वो आम आदमी का क्या सम्मान करेगा? क्या कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ये भूल गए कि - जनजातीय समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी के विरुद्ध उन्होंने राष्ट्रपति का कैंडिडेट उतारा था। वो क्यों? इसीलिए न ताकि कोई जनजातीय समाज का व्यक्ति सर्वोच्च आसंदी पर न बैठ सके। विपक्ष को क्या लगता है कि देश और बिहार की जनता ये सब नहीं देख रही थी? भला, हार मिलने पर –अपने कृत्य क्यों भूल जाते हैं?

वहीं परिवारवाद के शीर्ष उदाहरण राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव– ये सब क्या ये नहीं जानते हैं कि जनता अब 'परिवारवाद' को उखाड़ फेंक चुकी है। तिस पर भ्रष्टाचारी लालू परिवार। जंगलराज के आतंक का खौफ, लालू यादव की विवशता। धर्मनिष्ठ आचरण वाले तेजप्रताप यादव जैसे भाई का निष्कासन, आरजेडी पर कब्जा और लालू की विवशता भरी ईसाइयत से रंगी 'हैलोवीन' पार्टी। बिहार की जनता ये सब बारीकी के साथ देख रही थी। बिहार की जनता ये जान रही थी कि कैसे तेजस्वी यादव के यहां अब ईसाईयत और मिशनरीज का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हिंदू परंपराओं को किनारे कर चोट पहुंचाई जा रही है। अन्यथा राजनीतिक फायदे के लिए 'छठी मैया' का राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपमान किया था। बिहार की जनता ये जान रही थी कि किसकी शह पर खेसारी जैसे दोयम दर्जे के लोग – श्रीराममंदिर पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। क्या तेजस्वी यादव इन सबका विरोध नहीं करते?

वस्तुतः ये परिणाम चीख-चीख कर यही कह रहे हैं कि -जनता विपक्ष की नीयत के खोट को

अच्छी तरह से जान-पहचान चुकी है। इसीलिए जनता अपने मतदान के जरिए इन दलों की नियति में हर बार खोट का सर्टिफिकेट लगा देती है। र-क-फ़ एश्ट हैक और वोट चोरी के मिथ्या आरोपों को जनता अच्छी तरह जान चुकी है।

जनता ने केन्द्र की मोदी सरकार आने के बाद विकास की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पाया है। विभिन्न योजनाओं की DBT के जरिए यानी सीधे खाते में राशि पहुंचने से लाभ पाया। शासन-प्रशासन में हर वर्ग और समाज का समुचित प्रतिनिधित्व देखा है। देश की जनता ने ये पुख्ता कर लिया है कि उसका वास्तविक हितैषी कौन है। उसने ये जाना है हिन्दू और हिंदुत्व का वास्तविक पक्षधर कौन है। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को त्याज्य मानता है। वोटबैंक के लिए अपमानित करता है। वो तो उसका हितैषी कभी नहीं हो सकता है। जनता अब तत्कालिक लाभ की दृष्टि से ही नहीं बल्कि दूरदर्शिता के साथ अपने निर्णय लेती है। वो ये जान चुकी है कि वास्तव में देश की बागडोर किसके हाथों में सुरक्षित है। 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति स्वीकार्यता के ये आंकड़े उपरोक्त बातों को बारंबार सिद्ध कर रहे हैं। अगर कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों को लगता है कि वो हवा-हवाई वादों के जरिए उसे बेवकूफ बना सकते हैं। भारत की अस्मिता पर प्रहार कर सत्ता पर आ सकते हैं। ऐसे में उन राजनीतिक दलों, नेताओं से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि निष्पक्षता का चोला ओढ़कर – पेड वर्कर की तरह काम करने वाले, यूट्यूबर्स– उनका माहौल बना सकते हैं। जनता के दिलों में जगह बना सकते हैं तो ये भ्रम भी तोड़ लें। क्योंकि देश की जागरुक जनता अपना हानि-लाभ अच्छी तरह से जानती है। राजनीतिक दलों, विश्लेषकों, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों से बेहतर अपने भविष्य का आंकलन करती है। उसके बाद ही मतदान करती है। अतएव अब अपने आपको कोई गलत-फहमी में न रखें। क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। साथ ही जनादेश को अपमानित करने का भी कुकृत्य न करें। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मीठा-मीठा, गप-गप, कड़वा-कड़वा- थू..थू। ये जनता अगर विपक्ष के तमाम हथकंडों के बावजूद भी अगर उस पर विश्वास नहीं जता रही है तो ये आत्मचिंतन का वक्त है। न कि जनादेश पर लांछन लगाने का समय है। अगर विपक्षी दल अब भी नहीं समझे तो उन्हें रसातल में हमेशा के लिए दफ्न होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA गठबंधन का विजयरथ एक बड़ी आश्वस्ति लिए हुए है। ये विजय रथ विपक्षी दलों ही नहीं अपितु भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों को भी हर बार चित करता है। जब दुनिया भारत को कमजोर करने की साजिश रचती है। जार्ज सोरोस जैसे तमाम भारत विरोधी लोग और शक्तियां– मोदी को उखाड़ फेंकना चाहती हैं। उस समय देश के अंदर एक अदृश्य शक्ति का संचार होता है। जो संजीवनी की भांति मोदी की राजनीतिक शक्ति को और मजबूत करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार की ये प्रचंड जीत केवल चुनावी जीत नहीं है। ये जीत केवल किसी राज्य की राजनीतिक सत्ता की जीत की तरह नहीं देखी जानी चाहिए। बल्कि इन जीतों में जो संदेश छुपा है। देश की जनता का मन और उसका भाव छिपा है। उसके निहितार्थ को भी समझने की जरुरत है। क्योंकि नियति ने 21 वीं सदी को भारत की सदी लिखा है। इसीलिए ये तमाम संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं।

बिहार का जनादेश: एनडीए की सुनामी में ध्वस्त हुआ महागठबंधन

अनादि शुक्ल

बिहार की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंची है, जहां मतदाता ने अपनी पसंद को अभूतपूर्व स्पष्टता, दृढ़ता और राजनीतिक परिपक्वता के साथ दर्ज किया है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सामान्य जनादेश नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश है, जहां नीतीश कुमार के सुशासन ने अविश्वास को पछाड़ दिया, स्थिरता ने प्रयोगधर्मिता को और सामाजिक सुरक्षा ने जातीय ध्रुवीकरण को दृढ़ता से मात दे दी। बिहार का यह जनादेश बताता है कि बिहार का मतदाता भावनात्मक राजनीति, जातिगत उत्तेजना और चुनावी वादों की चमक-दमक से परे निकल चुका है और वह केवल उसी नेतृत्व को स्वीकार करता है, जो उसके जीवन में वास्तविक बदलाव लाए, सुरक्षा दे, भरोसा कायम रखे और विकास को धरातल पर उतारे। इसी कसौटी पर यह समझना कठिन नहीं कि एनडीए को ऐतिहासिक जीत क्यों मिली और महागठबंधन क्यों धराशायी हो गया। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है पर चुनाव परिणामों ने स्पष्ट किया कि यह सीमा इस बार महज एक गणितीय संख्या बनकर रह गई। एनडीए बहुमत से कहीं आगे निकल गया जबकि महागठबंधन का प्रदर्शन तमाम पूवार्नुमानों से बहुत नीचे रह गया, जो 50 सीटें भी हासिल नहीं कर सका। तेजस्वी यादव, जो दो वर्षों से स्वयं को मुख्यमंत्री-इन-वेटिंग के रूप में प्रक्षेपित करते रहे, जनता द्वारा स्पष्ट तौर पर नकार दिए गए। यह हार केवल किसी एक नेता की नहीं बल्कि पूरी उस राजनीतिक रणनीति की असफलता है, जो जातीय समीकरणों, लुभावने लेकिन अवास्तविक वादों और सहयोगियों को हाशिये पर रखकर बनाई गई थी। 2020 में महज कुछ हजार वोटों से पीछे रहने वाली आरजेडी को इस बार उम्मीद थी कि वह आसानी से सत्ता के द्वार तक पहुंच जाएगी लेकिन 2025 ने उसका यह सपना ध्वस्त कर दिया।

इस चुनाव में महागठबंधन की सबसे बड़ी गलती टिकट वितरण की रणनीति रही। आरजेडी ने 144 सीटों में से 52 यादव उम्मीदवार उतारे, जो कुल टिकटों का लगभग 36 प्रतिशत थे। यह संख्या 2020 के मुकाबले कहीं अधिक थी। तेजस्वी यादव का उद्देश्य भले ही अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करना रहा हो लेकिन इसका परिणाम उलटा निकला। यादव बिहार की आबादी का मात्र 14 प्रतिशत हैं जबकि चुनाव का फैसला ईबीसी, महादलित, सवर्ण, युवा, महिलाएं, शहरी एवं आर्थिक रूप से

कमजोर वर्गों पर निर्भर करता है। इतने अधिक यादव प्रत्याशी उतारने से यह संदेश गया कि आरजेडी सत्ता को फिर से एक जाति के हाथों में सौंपना चाहती है। एनडीए ने इसे चुनावी हथियार बनाकर 'यादव राज-भाग 2' का नैरेटिव चलाया, जो शहर से गांव तक गूंजता हुआ जनमत को प्रभावित करता गया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 में जातिगत संतुलन साधते हुए केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे थे, जिससे व्यापक सामाजिक आधार मिला। तेजस्वी इससे सीख नहीं ले सके और आरजेडी की छवि और भी यादव-केंद्रित बन गई, जिसका सीधा असर 10 से 15 प्रतिशत वोटों के खिसकने के रूप में सामने आया।

दूसरी बड़ी गलती गठबंधन प्रबंधन की विफलता रही। महागठबंधन ऊपरी तौर पर भले ही मजबूत दिखता रहा लेकिन भीतर से बिखरा हुआ था। कांग्रेस से सीट-बंटवारे पर तकरार, वाम दलों को कमजोर सीटें देना और सहयोगियों को प्रचार में हाशिये पर रखना, इन सबने गठबंधन में असंतोष पैदा किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब महागठबंधन का घोषणापत्र 'तेजस्वी प्रण' के नाम से जारी किया गया। यह कदम साझेदारी की भावना को ठेस पहुंचाता था। कांग्रेस गारंटी मॉडल पर केंद्रित थी, वाम दल मजदूर-किसान मुद्दों को उभार रहे थे लेकिन तेजस्वी केवल नौकरियों के वादे पर टिके रहे। महागठबंधन एक साझा दृष्टि से वंचित रहा और चुनावों में एकजुट चेहरा न बन सका। तेजस्वी की तीसरी चूक उनके वादों के अविश्वसनीय स्वरूप में दिखी। उन्होंने हर घर में नौकरी, पेंशन, शराबबंदी की समीक्षा, महिलाओं की बड़ी आर्थिक मदद जैसे भारी-भरकम वादे तो किए पर उनके क्रियान्वयन, वित्तीय स्त्रोत या समय सीमा पर कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दे सके। हर मंच से वे कहते रहे कि ब्लूप्रिंट जल्दी आ जाएगा लेकिन चुनाव समाप्त होने तक वह ब्लूप्रिंट नहीं आया। इससे उनकी विश्वसनीयता पर गहरा आघात हुआ, खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं में।

महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि ने नुकसान को और बढ़ाया। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो लाभ मिला पर पूरे राज्य में यह छवि प्रतिकूल साबित हुई। वक्फ बिल को लागू न करने की तेजस्वी की घोषणा और कई संवेदनशील बयानों ने यादव समुदाय के एक वर्ग को भी असहज कर दिया। एनडीए ने इसे भुनाया और लालू यादव के संसद में दिए भाषणों को वायरल कर जनमत को प्रभावित किया।

गैर-मुस्लिम और गैर-यादव वोटों ने निर्णायक मोड़ पर महागठबंधन को छोड़ दिया। तेजस्वी यादव की सबसे जटिल रणनीतिक गलती उनके पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर उनकी दोहरी राजनीति रही। उन्होंने लालू की विरासत का सहारा भी लिया और उससे दूरी भी बनाए रखी। पोस्टरों में पिता की तस्वीर छोटी रखी गई जबकि मंचों पर उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। यह दोहरापन मतदाता को भ्रमित करता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेजस्वी पर 'लालू के पाप छिपाने' का आरोप लगाना इस उलझन को और गहरा कर गया।

इसके विपरीत एनडीए ठोस काम और प्रामाणिक शासन मॉडल के साथ मैदान में उतरा। नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में महिला-सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की जो नींव रखी थी, वही इस चुनाव में निर्णायक बनी। 2006 में शुरू हुई साइकिल योजना, किताब-धन, पोशाक-धन, छात्रवृत्ति, जीविका समूहों का विस्तार, इन सबने महिला मतदाताओं के मन में एक स्थायी भरोसा पैदा किया। 2025 के चुनाव में महिलाओं का मतदान पुरुषों से 9 प्रतिशत अधिक रहा, जो स्पष्ट संकेत था कि महिला मतदाता एनडीए के साथ खड़ी हैं। जीविका समूहों से जुड़ी एक करोड़ से अधिक महिलाओं पर आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभाव सीधा मतदान व्यवहार पर पड़ा। 10,000 रुपये की सहायता और 2 लाख रुपये तक की उद्यम सहायता ने इन्हें राजनीतिक रूप से और भी सक्रिय बनाया।

दलित और अति पिछड़ी महिलाओं का समर्थन भी निर्णायक रहा। महागठबंधन की ऊंची-ऊंची घोषणाओं के विपरीत एनडीए की योजनाएं उनके जीवन में ठोस बदलाव ला रही थी, जिससे जातीय ध्रुवीकरण की संभावित रणनीति भी ध्वस्त हो गई।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कानून-व्यवस्था का रहा। बिहार 2005 से पहले जिस बदहाल सुरक्षा व्यवस्था से गुजर रहा था, उसे नीतीश कुमार के शासन ने बदल दिया। अपराध में आई गिरावट, सड़क-बिजली में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रात में भी महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही, ये सब बातें बिहार के सामाजिक मानस में गहराई से दर्ज हैं।

एनडीए ने इसका चुनावी लाभ उठाया और जनता ने इसे स्वीकार किया। 2025 का चुनाव इस सबसे महत्वपूर्ण सबक को दोहराता है कि लोकतंत्र में सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि नेतृत्व की विश्वसनीयता मायने रखती है। तेजस्वी युवा और ऊजार्वान हैं लेकिन वे अभी उस परिपक्वता, ठोस दृष्टि और स्थिरता वाले नेतृत्व का विकल्प नहीं बन पाए, जिसकी उम्मीद बिहार का मतदाता करता है। आरजेडी का जाति-केंद्रित चुनाव, महागठबंधन की विफल रणनीति और तेजस्वी की नीतियों का धुंधलापन, इन सबने मिलकर परिणाम तय कर दिए। कुल मिलाकर, यह जनादेश केवल एनडीए की जीत नहीं बल्कि बिहार के मतदाता की राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। यहां जनता ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह सिर्फ सरकार नहीं, विश्वास चुनती है।

बिहार में सीएम योगी का चला सिक्का
अखिलेश साबित हुए खोटा सिक्का

अनिल वशिष्ठ

योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के लगभग 43 विधानसभा क्षेत्रों में 31 रैलियां और 1 रोड शो किया, जहां उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों की मजबूती के लिए वोट मांगे। उनकी जनसभाएं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, पूर्णिया जैसे महत्वपूर्ण जिलों में हुईं, जहां उनकी लोकप्रियता के चलते अधिकांश क्षेत्र एनडीए के पक्ष में रहे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने साफ तौर पर अपना दबदबा दिखाया जबकि अखिलेश यादव की कोशिशें महागठबंधन के पक्ष में खास असर नहीं दिखा सकीं। चुनाव के नतीजों में एनडीए गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन अपेक्षित सफलता से बहुत पीछे रहा। यह चुनाव बिहार की राजनीति में भाजपा-जेडीयू के गठबंधन की मजबूती और विपक्ष की कमजोरी का परिचायक रहा। चुनाव परिणामों के अनुसार, एनडीए को लगभग 124 से 146 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि महागठबंधन के पक्ष में मात्र 73 से 77 सीटें ही रहीं। यह स्पष्ट हुई कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच गठबंधन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एनडीए की रणनीति रही कि विकास, कानून-व्यवस्था और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को सामने रखा जाए, जिसने आम मतदाताओं में गहरा प्रभाव डाला। इसके विपरीत, महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल थे, ने अपेक्षित सीटें नहीं

जीत पाई और उनकी लोकप्रियता सीमित रही।

योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के लगभग 43 विधानसभा क्षेत्रों में 31 रैलियां और 1 रोड शो किया, जहां उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों की मजबूती के लिए वोट मांगे। उनकी जनसभाएं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, पूर्णिया जैसे महत्वपूर्ण जिलों में हुईं, जहां उनकी लोकप्रियता के चलते अधिकांश क्षेत्र एनडीए के पक्ष में रहे। योगी के प्रचार क्षेत्रों में भाजपा और जेडीयू उम्मीदवारों ने दमदार जीत हासिल की, जो उनके प्रभाव और कड़ी मेहनत का परिणाम था। वहीं, अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए छह बड़ी जनसभाएं की और पूर्वी बिहार के जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, सिवान, कैमूर और पटना में प्रचार किया। हालांकि उनकी ये कोशिशें महागठबंधन के पक्ष में फायदा नहीं पहुंचा सकीं। प्रचार के बावजूद महागठबंधन उम्मीदवारों को उनमें से अधिकांश सीटों पर या तो हार का सामना करना पड़ा या उनके मत करीब रहा, लेकिन जीत नहीं मिली।

एनडीए की सफलता का एक कारण यह भी था कि उन्होंने जाति, सामाजिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर बेहतर समन्वय किया। मोदी-योगी की जोड़ी ने प्रदेश में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था सुधारों, और सामाजिक न्याय के संदेश के साथ एक मजबूत चुनाव अभियान चलाया। इसने मतदाताओं के बीच एक नकारात्मक मत भी लगाया जो महागठबंधन के खिलाफ गया। इसके अलावा, स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर भी कड़ी मेहनत की, जिससे वोट बैंक सक्रिय हुआ। चुनाव में प्रमुख सीटों पर हुए नतीजों में दरभंगा, भागलपुर, पटना, बोचाहा, पूर्णिया जैसी सीटों पर योगी के प्रचार क्षेत्र में भाजपा और जेडीयू के पक्ष में जीत मिली जबकि अखिलेश के प्रचार क्षेत्रों जैसे बक्सर, सिवान, कटिहार में भी एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया। परिणामस्वरूप एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है।

इस तरह बिहार चुनाव 2025 में मोदी-योगी की जोड़ी ने अपने प्रचार-प्रसार के दम पर चुनावी मंथन में एनडीए गठबंधन को विजय दिलाई, जबकि अखिलेश यादव और उनका महागठबंधन कमजोर पड़ा। यह चुनाव बिहार की राजनीति में एनडीए के प्रभाव और विपक्ष की चुनौतियों का संकेत है। आने वाले समय में बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस चुनाव के परिणामों का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा।

अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए छह बड़ी जनसभाएं की और पूर्वी बिहार के जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, सिवान, कैमूर और पटना में प्रचार किया। हालांकि उनकी ये कोशिशें महागठबंधन के पक्ष में फायदा नहीं पहुंचा सकीं। प्रचार के बावजूद महागठबंधन उम्मीदवारों को उनमें से अधिकांश सीटों पर या तो हार का सामना करना पड़ा या उनके मत करीब रहा, लेकिन जीत नहीं मिली।

समाजवाद से दूरी ने कहीं का नहीं छोड़ा

अरुण शर्मा

बिहार में एनडीए की जीत को अपने-अपने नजरिए से देखा और विश्लेषित किया जा रहा है। बिहार में एनडीए की जीत के पीछे किसी को चुनाव आयोग की मिलीभगत दिख रही है तो किसी को सत्ता का दुरूपयोग तो कोई इसे भीतरघात के रूप में देख रहा है। लेकिन किसी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बिहार के पूरे प्रचार अभियान में सत्ता के दावेदार विपक्षी गठबंधन ने कितनी बार कपूर्री ठाकुर का नाम लिया, लोहिया की सप्त क्रांति की बात छोड़िए, कितनी बार जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की चर्चा हुई? यह सवाल इसलिए जरूरी और वाजिब लगता है, क्योंकि महागठबंधन की अगुआई जो राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है या कर रहा था, घोषित तौर पर लालू प्रसाद यादव उसके प्रमुख हैं। जो नहीं जानते हैं, उनके लिए यह बताना जरूरी है कि लालू यादव जिस आंदोलन की उपज माने जाते हैं, उस जेपी आंदोलन के अगुआ जयप्रकाश नारायण रहे हैं। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल घोषित तौर पर समाजवादी विचारधारा वाला दल है।

जिस तरह लालू परिवार की सिरफुट्टौवल की बातें चारदीवारी से बाहर आ रही हैं, उससे साबित हो रहा है कि लालू अपनी पार्टी के सिर्फ कहने भर के अध्यक्ष हैं। पार्टी पर उनकी बजाय तेजस्वी यादव की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। एक तरह से कह सकते हैं कि तेजस्वी ही इस पार्टी के मालिक हैं। तेजस्वी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, उन्हें तपी-तपाई समाजवादी विचारधारा से कुछ लेना-देना नहीं है। पार्टी भले ही घोषित रूप से समाजवादी हो, लेकिन हकीकत में पार्टी पर वामपंथी वैचारिक धारा का कब्जा है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज का नाम घर से बाहर निकाले गए तेजप्रताप यादव ने कभी खुलकर नहीं लिया, लेकिन घर से बेआबरू होकर निकली लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी ने दोनों का खुलकर नाम ले लिया है। वैसे बिहार में पहले से ही चर्चा थी कि तेजस्वी को इन्हीं दोनों नामों पर भरोसा है। पता नहीं, इन दोनों ने हाथ तेजस्वी कौन की नस दबी है, लेकिन अब साफ हो गया है कि परिवार की कीमत पर अगर तेजस्वी इन पर भरोसा करते हैं तो तय है कि इसके पीछे कुछ न कुछ गंभीर कारण जरूर हैं। उनकी सियासी प्रतिभा नहीं। अगर उनकी सियासी प्रतिभा होती तो बेशक तेजस्वी आज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन कम से शर्मनाक हार के किनारे पर उनका दल नहीं पहुंचा होता। जनता दल से अलग राष्ट्रीय जनता दल गठित करते वक्त ही तय हो

गया था कि समाजवादी दर्शन की खोल में राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद का परचम लहराने की कोशिश करेगा। उसने लहराया भी, लेकिन उसने गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के नाम का मुखौटा धारण किए रखा। 2025 का विधानसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव रहा, जिसमें ना तो टीवी और अखबारी चचाओं में इस दल ने लोहिया, जयप्रकाश या कपूर्री ठाकुर का नाम लिया, ना ही मैदानी चुनावी सभाओं में इस पर फोकस किया गया। राष्ट्रीय जनता दल का टेलीविजन चैनलो पर पक्ष रखने के लिए तीन महिलाएं आगे कर दी गईं। प्रियंका भारती, कंचना यादव और सारिका पासवान को सौम्य और मृदु मृत्युंजय तिवारी और पढ़ाकू बौद्धिक मनोज झा के मुकाबले तवज्जो दी गई। तीनों महिलाएं बहस कम, बदतमीजी ज्यादा करती दिखीं। उन्हें लगा कि दबंग आवाज में अपनी बात रखेंगे तो वह दूर तक सुनी जाएगी। इन्होंने अपने विपक्षी नेताओं को खुलेआम अपशब्द कहे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की।

आधुनिक टेलीविजन विमर्श के बड़े और गंभीर चेहरे सुधांशु त्रिवेदी से प्रियंका ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कंचना ने तो शुभ्रास्था के साथ सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया। प्रियंका और कंचना भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लालगढ़ के रूप में विख्यात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं। यह ठीक है कि जेएनयू पढ़ाई का संस्कार तो देता है, लेकिन उसका संकट यह है कि वह भारतीय समाज को वामपंथी चश्मे से देखने और समझने का जबर्दस्ती संस्कार थोप देता है। इसलिए यहां की वामपंथी राजनीति में पगा-डूबा छात्र समाज की हर समस्या के मूल को रामास्वामी पेरियार और महात्मा फुले के वैचारिक दर्शन के ही सहारे ढूंढ़ता है और उनके ही सुझाए अतिवादी विचारों के जरिए उन्हें सुलझाने की समझ विकसित करता है। प्रियंका और कंचना जेएनयू की उसी परंपरा में पगी-डूबी छात्रा हैं, इसलिए वे बिहार के समाज को भी उसी अंदाज में समझ रही थीं और अपने हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को उसी नजरिए से आगे बढ़ा रही थीं। इसका असर यह हुआ कि जिस बिहार की धरती से भारतीय समाजवाद ने राजनीतिक गलियारों तक की सफल यात्रा की थी, जिसके उत्तराधिकारी खुद लालू यादव भी रहे हैं, उस समाजवाद का सार्वजनिक विमर्श में भूले-भटके

भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस कपूर्री ठाकुर की राजनीति के उत्तराधिकारी लालू रहे, उनका भी नाम नहीं लिया गया। जेपी और लोहिया की तो बात ही और है। सवाल यह है कि लालू की पार्टी का जो कट्टर समर्थक यादव समुदाय है, क्या वह सचमुच पेरियारवादी है, वह फुले के वैचारिक दर्शन को मानता है। पेरियार और फुले जिस ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना करते हैं, राजनीति को छोड़ दें तो यादव समाज भी वास्तविक जीवन में उतना ही ब्राह्मणवादी है।

वह भी हिंदू है और कई बार तो कथित सवर्ण समाज से भी कहीं ज्यादा हिंदू है। वह भी उसी तरह पूजा-पाठ करता है, उसी तरह धार्मिक है, उसी तरह पारिवारिक संस्कार करता है, जैसा बाकी कथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम मंदिर की आलोचना करना, छठ पूजा पर सवाल उठाना क्या आम यादव समुदाय को स्वीकार्य हो पाया होगा? वैसे राबड़ी देवी ने छठ पूजा छोड़ दी है। लेकिन उनकी छठ पूजा भी कभी बिहार के मीडिया माध्यमों के लिए बड़ी खबर बनी रहती थी। तेजप्रताप को राजद के इस विचलन का पता था, शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपील कर दी थी कि अब तेजस्वी जी की पत्नी को छठ पूजा का व्रत शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि बिहार में सास से बहू छठ पूजा का उत्तराधिकार हासिल करती है। बहरहाल चुनाव नतीजों ने तो बता दिया कि बिहार में विपक्षी गठबंधन जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर करने की कोशिश कर रहा था या दूर मान रहा था, वह भी दरअसल उसकी सोच के दूसरे बिंदु पर खड़ा है।

सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल से समाजवाद की विदाई क्यों हुई? इस सवाल का जवाब तलाशना कोई राकेट साइंस नहीं है। वामपंथी वैचारिकी के करीब होने के साथ ही तेजस्वी उस राहुल गांधी के भी करीब हैं, जिन्हें हर समस्या का समाधान वामपंथी सोच में ही नजर आती है। हिंदुत्व का विरोध उनका प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। तेजस्वी भी यही कर रहे थे। इसे बढ़ावा देने में उनके सलाहकारों संजय यादव और रमीज ने भरपूर मदद दी है। प्रियंका, कंचना और सारिका जैसी बदमिजाज प्रवक्ताओं को प्रश्रय संजय यादव और रमीज की ही शह पर दिया गया। हर घर में सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी के वायदे के पीछे वामपंथी अतिवादी वैचारिकी का ही हाथ रहा, नतीजा सामने है। बिहार की सत्ता छींका की तरह तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो गई है। पेरियार और फुले की वैचारिकी पर आधारित राष्ट्रीय जनता दल अगर आने वाले दिनों में बिखराव की ओर चल पड़े तो हैरत नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक बिखराव तो खैर शुरू हो ही चुका है।

प्रदूषण की कीमतः क्या भारत को चाहिए एक व्यापक 'प्रदूषण कर'?

भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेज आर्थिक विकास और बिगड़ते पर्यावरण के संकट के बीच संतुलन बनाना अत्यंत कठिन चुनौती बन गया है। शहरों की हवा दिन-प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है, नदियाँ औद्योगिक कचरे से भर रही हैं, भूमिगत जल स्तर घट रहा है, ठोस कचरे के पहाड़ महानगरों की पहचान बनते जा रहे हैं, वहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब भारत को प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रत्यक्ष आर्थिक दंड लगाने–अर्थात् विस्तृत 'प्रदूषण कर' लागू करने–की आवश्यकता है?

प्रदूषण कर का विचार नया नहीं, परन्तु इसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब कोई उद्योग, वाहन या गतिविधि प्रदूषण फैलाती है तो उसका

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, न कि केवल उसे जो प्रदूषण फैला रहा है। यह बाजार व्यवस्था की वह गंभीर विफलता है जिसे 'बा' लागत' कहा जाता है–अर्थात् नुकसान तो समाज को होता है, पर उसका मूल्य न तो वस्तु की कीमत में जुड़ता है, न ही प्रदूषण फैलाने वाला उसे भरता है। ऐसे में 'प्रदूषण कर' इसी असंतुलन को सुधारने का प्रयास करता है, जहाँ जो जितना अधिक प्रदूषण फैलाए, वह उतनी अधिक आर्थिक कीमत चुकाए।

भारत में कोयले पर लगाया गया 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' इसका एक प्रारंभिक स्वरूप था, परंतु आज देश में वायु, जल, ध्वनि, ठोस कचरा और औद्योगिक उत्सर्जन का ऐसा मिश्रित संकट है कि केवल किसी एक क्षेत्र पर कर लगाना पर्याप्त नहीं। आवश्यकता एक सर्वसमावेशी और वैज्ञानिक पद्धति से तैयार प्रदूषण कर की है, जो प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने में सहायक हो।

प्रदूषण कर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रदूषण को महँगा बनाता है और स्वच्छता को सस्ता। जब किसी उद्योग को प्रति इकाई उत्सर्जन पर कर देना पड़ेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी तकनीक अपनाने की ओर अग्रसर होगा जो कम प्रदूषण करे। यूरोप जैसे क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है जहाँ कार्बन-आधारित दंड के बाद ऊर्जा-संरक्षण और हरित तकनीक का उपयोग अत्यधिक बढ़ा। भारत में भी यह परिवर्तन संभव है, बशर्ते नीति दीर्घकालिक, पारदर्शी और लक्ष्य-उन्मुख हो। दूसरा

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत को आने वाले वर्षों में पर्यावरण-रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। नदियों की सफाई, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा हरित भवनों के विकास पर अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रदूषण कर एक स्थायी और अनुमानित राजस्व स्रोत बन सकता है, जिसे एक स्वतंत्र 'हरित निधि' के माध्यम से केवल पर्यावरण संरक्षण पर व्यय किया जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर भी प्रदूषण कर का महत्व बढ़ रहा है। कई विकसित देश अब उन आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगा रहे हैं जो अधिक प्रदूषणकारी स्रोतों से बनती हैं। यदि भारत घरेलू स्तर पर प्रदूषण पर उचित कर लागू करता है, तो भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाजारों में अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सकती है। इस प्रकार प्रदूषण कर केवल पर्यावरण-हित में नहीं, बल्कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा की रक्षा में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। परंतु इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रदूषण कर गरीबों पर भारी पड़ सकता है? यह चिंता बिल्कुल वास्तविक है। यदि ईंधन और बिजली की लागत बढ़ेगी, तो उसके साथ ही परिवहन, खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव निम्न-आय वर्ग पर पड़ता है, जिनके पास विकल्प सीमित होते हैं। इसलिए प्रदूषण कर को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह अनिवार्य होगा कि निम्न-आय वाले परिवारों को प्रत्यक्ष नकद सहायता, ऊर्जा सब्सिडी और रसोई गैस जैसी आवश्यकताओं पर राहत दी जाए। उद्योग जगत की चिंताएँ भी कम नहीं। विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ऊर्जा-प्रधान होते हैं और किसी भी अतिरिक्त कर का प्रभाव उनकी लागत पर पड़ता है। अतः प्रदूषण कर को चरणबद्ध ढंग से लागू करना होगा—पहले बड़े उद्योगों पर, फिर धीरे-धीरे छोटे उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इस दायरे में लाना होगा। हरित मशीनरी पर अनुदान, ब्याज रहित ऋण, और तकनीकी उन्नयन के लिए मार्गदर्शन इस परिवर्तन को सुगम बना सकते हैं।

भारत की प्रशासनिक क्षमता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रदूषण का सटीक मापन, डेटा की विश्वसनीयता और निगरानी तंत्र की पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक होगी। छोटे उद्योगों और गैर-प्रमाणित स्रोतों की निगरानी आज भी चुनौतीपूर्ण है। यदि उत्सर्जन मापन ही विश्वसनीय न हो, तो कर प्रणाली पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को आधुनिक सेंसर-तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डिजिटल उत्सर्जन-पंजीकरण तथा रियल-टाइम निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रदूषण कर की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार इसके राजस्व का उपयोग कहाँ करती है। यदि यह धन सामान्य बजट में विलीन हो गया, तो जनता में अविश्वास बढ़ेगा और नीति का उद्देश्य कमजोर पड़ेगा। इसके लिए एक स्वतंत्र 'हरित कोष' का गठन आवश्यक है, जो केवल प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों पर व्यय हो तथा जिसकी वार्षिक लेखा-परीक्षा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। राजनीतिक दृष्टि से यह एक साहसिक कदम होगा। किसी भी प्रकार की मूल्य-वृद्धि जनता के बीच असंतोष उत्पन्न कर सकती है। परंतु यह भी सत्य है कि पर्यावरणीय संकट अब इतना गंभीर हो चुका है कि उससे निपटने के लिए कठोर, दीर्घकालिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधार आवश्यक हैं। भारत की युवा पीढ़ी सुरक्षित जल, स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन की मांग कर रही है। इस मांग को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रदूषण कर भारत के लिए केवल राजस्व-संग्रह का साधन नहीं, बल्कि एक व्यापक हरित परिवर्तन की दिशा में आवश्यक कदम है। इसे न्यायपूर्ण, पारदर्शी, चरणबद्ध और वैज्ञानिक आधार पर लागू करने से भारत न केवल प्रदूषण कम कर पाएगा, बल्कि अपने विकास मॉडल को भी टिकाऊ, स्वस्थ और पर्यावरण-सम्मत बना सकेगा। यदि इसे सही नीतिगत ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत के इतिहास में वह मोड़ साबित हो सकता है जहाँ देश ने आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी सिद्ध किया।

अब 'फेफड़े वालों' की भी नहीं रही दिल्ली?

हर साल नवंबर का महीना आते ही देश की राजधानी दिल्ली एक 'गैस चैंबर' में तब्दील हो जाती है। नवंबर 2025 में एक बार फिर दिल्लीवासियों का सांस लेना दूभर हो गया है। सुबह की शुरूआत ताजी हवा से नहीं, बल्कि धुंध की एक मोटी चादर और आंखों में जलन के साथ हो रही है। लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के विशेषज्ञों ने इसे 'मेडिकल इमरजेंसी' करार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि लोक स्वास्थ्य का बड़ा खतरा बन गया है।

वर्तमान स्थिति के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 के मध्य में दिल्ली के कई इलाकों (जैसे बवाना, वजीरपुर, और जहांगीरपुरी) में अदक 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में दर्ज किया गया है। कुछ स्थानों पर यह 500 के खतरनाक स्तर को भी छू रहा है। स्थिति को देखते हुए 'ग्रैप' (grap graded response action plan) के कड़े चरण लागू किए गए हैं, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक और इर-क्क्क्क पेट्रोल व इर-क्क्क डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध शामिल हैं।परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान का समर्थन करते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंधित सभी गतिविधियों पर साल भर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को दोनों राज्यों में पराली जलाने के मुद्दे पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निदेर्शों का सख्ती से पालन करने को कहा।

अदकबताता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। जब AQI 0 से 50 के बीच होता है, तब हवा अच्छी मानी जाती है और सेहत पर कोई असर नहीं होता।51 से 100 के बीच हवा संतोषजनक होती है, जिससे बहुत संवेदनशील लोगों को थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो सकती है। 101 से 200 के बीच हवा मध्यम होती है, जो फेफड़ों, अस्थमा या हृदय की बीमारी वाले लोगों को दिक्कत दे सकती है। 201 से 300 तक की हवा खराब होती है और लंबे समय तक इसमें रहने से अधिकतर लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। 301 से 400 के बीच हवा बहुत खराब होती है, जिससे लोगों को सांस की बीमारियां हो सकती हैं। जब अदकका लेवल 400 के पार पहुँच जाता है, जैसा कि इन दिनों हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हवा में मौजूद PM 2.5 के सूक्ष्म कणों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँचा रही है। एक्सपर्ट का साफ अनुमान है कि ऐसे गंभीर प्रदूषण में बिना मास्क के बाहर निकलना या साँस लेना, एक दिन में 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है। जो स्वस्थ लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है और बीमार लोगों की हालत और बिगाड़ सकती है। एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण अब केवल अस्थमा, सांस फूलना और COPD तक सीमित नहीं है। हवा में मौजूद महीन कण रक्तप्रवाह में शामिल होकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम भी बढ़ा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से रोजाना 20 से 30 मरीज सांस और अन्य प्रदूषणजनित बीमारियों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। हवा में मौजूद अल्ट्रा-फाइन कण गर्भवती महिलाओं के शरीर के माध्यम से गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रहे हैं। इससे न केवल भ्रूण की वृद्धि प्रभावित होती है बल्कि कम वजन वाले बच्चों के जन्म और आगे चलकर फेफड़ों के कमजोर होने की आशंका भी बढ़ जाती है।

हाल ही में, एक प्रतिष्ठित भारतीय आर्थिक सेवा (IES) अधिकारी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति और अपने छोटे बेटे के स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी ग्रुप 'ए' सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बढ़ते प्रदूषण के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद केवल 'जीवन जीने' की बात नहीं करता, बल्कि एक गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट किया है कि 'जीवन का अधिकार' केवल जानवरों की तरह अस्तित्व में बने रहना नहीं है। बल्कि इसमें स्वच्छ हवा में सांस लेना,प्रदूषण मुक्त जल,स्वच्छ पर्यावरण में रहने जैसे अधिकार शामिल है। यदि प्रदूषण इतना बढ़ जाए कि वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने लगे, तो यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है।

बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाल ही में जंतर मंतर पर LetUsBreathe नामक एक विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें LetUsBreathe केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता को भी दर्शा रहा था। लोग इस बात से नाराज हैं कि हर साल उन्हें इसी जानलेवा स्थिति का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये गुस्सा इस मांग पर केंद्रित है कि स्वच्छ हवा को स्वास्थ्य के अधिकार के रूप में देखा जाए। दिल्ली का प्रदूषण अब एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक साल भर रहने वाला संकट बन रहा है जो सर्दियों में जानलेवा हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि साफ हवा हमारा अधिकार ही नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरत है। यदि आज हमने कड़े कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचेगा। यह समय 'चिंता' करने का नहीं, बल्कि 'चिंतन' और 'कार्रवाई' का है। आज की जहरीली हवा, कल की गंभीर बीमारी है।

वोट बैंक के कारण होते हैं धार्मिक आयोजनों में हादसे

आंध्र प्रदेश में काशीबुग्गा शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। मंदिर एक निजी तीर्थस्थल था, जो धर्मस्व विभाग के तहत पंजीकृत नहीं था। कार्यक्रम आयोजकों ने इतनी बड़ी भीड़ के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। देश में होने वाले धार्मिक आयोजनों में लापरवाही और कानून के उल्लंघन की सत्तारुढ़ दल और नेता अनदेखी करते रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह कि कहीं उनका वोट बैंक हाथ से नहीं खिसक नहीं जाए। इसलिए वे कानून उल्लंघन से होने वाले संभावित हादसों की अनदेखी करते हैं। अन्यथा यह संभव नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर किसी एक हादसे के बाद ऐसे हादसों की देश में पुनरावृत्ति होती रहे। वेकंटेश्वर मंदिर में हुआ हादसा इसका नया प्रमाण है।

ये पहली बार नहीं है, जब किसी मंदिर में ऐसा

मनोज शर्मा

हुआ हो, इससे पहले भी हजारों लोगों की ऐसी घटनाओं में दर्दनाक मौत हो चुकी है। साल 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में 350 से अधिक भक्तों की कुचलकर मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में साल 2008 में नैना देवी मंदिर मची भगदड़ में 162 की जान गई थी। 30 सितम्बर 2008 को राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम की अफवाह से मची में 250 श्रद्धालु मारे गए। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 39 लोग मारे गए। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोग मारे गए । भगदड़ की शुरूआत इस अफवाह से हुई कि जिस नदी के पुल को श्रद्धालु पार कर रहे थे, वह टूटने वाला है।

31 मार्च, 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन 'बावड़ी' या कुएं के ऊपर बनी स्लैब के ढह जाने से कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई। 14 जनवरी, 2011 को केरल के इडुक्की जिले के सबरीमाला में पुलमेदु में एक जीप से लौट रहे तीर्थ यात्रियों से टकरा गई, जिससे भगदड़ मच गई जिसमें कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह में पटना के गांधी मैदान में भगदड़ से 32 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के तट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल टूटने से लगभग 20 लोग मारे गए। 1 जनवरी, 2022 को जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से 12 लोगों की

मौत हो गई। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में 'पुष्करम' त्योहार के उद्घाटन के दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर-की-पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई थी। लोग स्वयंभू बाबा से मुफ्त कपड़े और भोजन लेने के लिए एकत्र हुए थे। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई 2025 को करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। 3 मई, 2025 को गोवा के शिरगांव गांव में श्री लाईराई देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान अचानक भगदड़ मचने से छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाकी रिपोर्ट्स में आंकड़े काफी ज्यादा बताए गए। इन हादसों में घायलों की संख्या भी हजारों में रही।

इन सभी हादसों में एक बात समान है कि भीड़ जमा हुई थी और लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन ऐसी घटनाएं बार-बार लौट कर पुराने हादसों के जख्म हरे कर देती हैं। बड़ा आयोजन, बड़ी भीड़ और बड़े हादसे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धार्मिक आयोजन में क्यों मचती है भगदड़ और कैसे मरते हैं लोग? अक्सर जब हादसे होते है, जांच रिपोर्ट सामने आती हैं तो प्रशासनिक गलती सामने आती है। आस्था, नाकाफी इंतजाम, कम जगह में ज्यादा श्रद्धालु और मौसम को दोषी ठहराया जाता है। कई हादसों की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जब भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते गए। रिपोर्ट में कई बार तो कहा गया कि अफरातफरी के बीच लोगों की मौत दम घुटने को लेकर हुई।

एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2019 के बीच देश दुनिया में भगदड़ की बड़ी घटनाएं हुए उनमें करीब 79 फीसदी मामले धार्मिक आयोजन के दौरान हुए थे। रिपोर्ट के अध्ययन के अनुसार भारत में धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के प्रमुख कारणों में भौगोलिक स्थान का विशेष महत्व है। भगदड़ की वजह पहाड़ी क्षेत्रों जैसे ढाल, दलदली इलाका, कीचड़ युक्त मैदान, खड़ी ढलान और बारिश से बचाव के इंतजाम न होने के चलते होता है। जबकि विदेशों में म्यूजिक कंसर्ट, स्टेडियम

और नाइट क्लबों में होता है। आयोजन स्थल पर भीड़ कितनी आएगी, स्थान विशेष पर कितना लोगों का दबाव होगा, इसकी सटीक जानकारी और बेहतर इंतजाम हो तो हादसे को कंट्रोल किया जा सकता है। कई तरीके हैं जिन्हें अपनाकर भीड़ काबू में की जा सकती है। इन हादसों को रोका जा सकता है, अगर क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें। भीड़ को दबाव को लाइन में लगाकर कम कर लें। भगदड़ की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम रखें और वीवीआईपी मेहमानों के लिए सही तरीके से आगमन का इंतजाम रखें। बैरिकेड लगाकर, स्नेक लाइन एप्रोच बनाकर भीड़ को काबू में किया जा सकता है। ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर भगदड़ के प्रभाव को न्यूट्रल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि घटनास्थल वाले जिले का प्रशासन इन उपायों से वाकिफ नहीं हो, किन्तु लापरवाही और धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप से नेताओं के वोट बैंक बिगड़ने का भय इसमें आड़े आता है। जब तक यह संकीर्ण सोच बनी रहेगी, तब तक ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होती रहेंगी।

बच्चों के अधिकार: दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी

रवि जैन

बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस 'मेरा दिन, मेरे अधिकार' विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को 'विश्व बाल दिवस' मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वी के कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में।

दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आइए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है।

जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में, 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में, 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलीस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्की, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाईजीरिया, मई के आखरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में,

1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्तूबर को ईरान, 12 अक्तूबर को ब्राजील, अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्तूबर के चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया, नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। बहरहाल, विश्व बाल दिवस पर हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं।

मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके और बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।

वेडिंग सीजन में दिखना है सबसे ग्लैमरस? भूमि का यह लहंगा लुक जरूर करें ट्राई!

भूमि पेडनेकर का हालिया पेस्टल पिंक लहंगा लुक वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई है। इस एलिगेंट भूमि पेडनेकर लहंगा में मॉर्डन कट ब्लाउज, डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी और स्टेटमेंट ज्वेलरी का शानदार मिश्रण है, जो आपको ग्लैमरस और रॉयल लुक दे सकता है।

बॉलीवुड डीवज के लुक्स इंस्पायर होकर आप भी फेस्टिव सीजन लेकर शादी के मौसम के लिए भूमि पेडनेकर का यह लहंगा लुक डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। फैशन लवर्स ट्रेडिंग लुक के लिए बॉलीवुड हीरोइन से प्रेरणा लेकर एक परफेक्ट ट्रेडिशनल आउटफिट को वियर कर सकते हैं। भूमि ने हाल ही में एक सुंदर-सा पेस्टल शेड के लहंगे में पोज देती नजर आई हैं। इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इस लुक में एक्ट्रेस एलिगेंट दिख रही है। मिनिमल मेकअप लुक, स्टेटमेंट ज्वेलरी और फ्लोई सिल्हूट के साथ उनका यह लहंगा वाकई सुंदर नजर आ रहा है। इस लहंगा लुक में एक्ट्रेस रॉयल लग रही है। आप भी इस लहंगा को अपने वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं। भूमि पेडनेकर लहंगा की खासियत-

पेस्टल पिंक का चयन

फोटो में आप देख सकते हैं कि भूमि ने पेस्टल पिंक शेड को चूज किया है। फेस्टिवल से लेकर वेडिंग तक यह रंग काफी काफी ट्रेंड में है। लहंगे पर डिलेकेट व्हाइट एम्ब्रॉयडरी पूरे लुक में एथनिक ग्रेस जोड़ता है। यह व्हाइट थ्रेडवर्क इस शेड के साथ बेहतरीन कंट्रास्ट बनाता है।

मॉर्डन कट ब्रालेट डिजाइन ब्लाउज

एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल चोली की जगह एक क्रोश-इफेक्ट, मॉडर्न कट ब्लाउज पहना है। यह लहंगा एकदम इंडो-वेस्टर्न लुक प्रदान करता है।

मैचिंग दुपट्टा और ड्रेपिंग स्टाइल

एक्ट्रेस ने सॉफ्ट पिंक शेड का दुपट्टा सिंगल-साइड ड्रेप किया गया है। यह इस लुक को एकदम मिनिमल रख रहा है।

स्टेटमेंट सिल्वर-टोन ज्वेलरी

एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने चोकर, ब्रेसलेट और स्टेटमेंट ईयरस्टड्स चुनें जो आउटफिट को ग्लैम लुक दे रही है। यह ज्वेलरी लहंगा के साथ मैच कर रही है।

नेचुरल मेकअप और हेयरस्टाइल

भूमि ने न्यूड लिप्स, ग्लोई बेस और मस्कारा-फोकस्ड आईज ने लुक को सॉफ्ट और मॉर्डन टच दिया है। वहीं, स्ट्रेट ओपन हेयर लहंगे की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है।

हेयर स्टाइलिंग के बावजूद बालों को टूटने से बचाएं! एक्सपर्ट से जानें इन्हें सुरक्षित रखने के खास तरीके

फैशन के लिए हीट स्टाइलिंग का प्रयोग करने वाली लड़कियों के लिए यह लेख बालों को कमजोर होने से बचाने के खास तरीके बताता है, जिसमें हीटिंग स्प्रे का उपयोग और घरेलू हेयर मास्क से पोषण शामिल है।

आजकल लड़कियां फैशन के लिए नई-नई हेयर स्टाइल को जरुर ट्राई करती हैं। वैसे भी बालों के अलग-अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाना हम सभी को बेहद पसंद है। कई बार होता है कि हीट स्टाइलिंग टूल्स का प्रयोग करके, बालों में बाउंस या स्ट्रेट बना सकते हैं।

अत्यधिक हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बाल कमजोर होने लगते हैं। कई बार तो बालों के लिए अलग-अलग ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं, जिससे बालों में पोषण बना रहे। अगर आपको बालों को स्ट्रांग कराना है, तो इन टिप्स को फॉलों करें।

हीट स्टाइलिंग से कमजोर हुए बालों को स्ट्रांग बनाने की टिप्स

जब भी आप हीट स्टाइलिंग टूल्स का प्रयोग कर रही हैं, तो आप हीटिंग सेटिंग स्प्रे का यूज

कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके बालों में हीट कम लगती है। इसके साथ ही आपके बाल खराब नहीं होते हैं। हीटिंग स्प्रे आपको बाजार में मिल जाएंगे। इसे पहले बालों में लगाकर फिर हीटिंग टूल्स का प्रयोग करें। इसके प्रयोग से आपके बाल डैमेज नहीं होंगे।

बालों को पोषण जरुर दें

यदि आप बालों में ज्यादा हीटिंग टूल का प्रयोग करती है, तो इससे पहले अपने बालों को पोषण जरुर दें। इसके लिए आप घर में बनें हुए सीरम या हेयर मास्क का प्रयोग कर सकती हैं। इसके बाद ही हीट स्टाइलिंग का इस्तेमाल करें।

ऐसा करने से आपका स्कैल्प कमजोर नहीं होगा और बाल भी मजबूत बनें रहेंगे। आपके हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। बस आपको समय-समय पर अपनी चीजों का इस्तेमाल करना जरुरी है।

रात को करें ये हेयर रुटीन फॉलो

अगर आपके हेयर्स हीटिंग टूल्स के प्रयोग से ज्यादा ही खराब हो रहे है, तो आप रात के समय हेयर केयर रुटीन जरुर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको बालों के टूटने की समस्या कम हो जाती है। आप हफ्ते में कम से कम 2 बार गरम तेल से बालों की मालिश करें। इसके बाद हेयर वॉश करें। ऐसा करने से आपके बालों को नमी मिलेगी।

रील और रियल लाइफ का संगम, ये शहर आपको देंगे फिल्मों सा भव्य अनुभव

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फिल्मी दुनिया में आ गए हैं। यहां की इमारतें, गलियां, कैफे और लोग सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जो आपको पूरी जिंदगी याद रहते हैं। वहीं फोटोग्राफी के लिहाज से भी यह जगहें बेस्ट हैं।

अरुण मिश्रा

घूमने-फिरने का शौक तो हर किसी को होता है। हर कोई ऐसी जगहों पर जाना चाहता है, जहां पर वह ढेरों यादगार पलों को इकट्ठा कर सकें। वहीं कुछ खास पलों को खुलकर एंजॉय कर सकें। दुनिया भर में कई ऐसे शहर हैं, जो किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं लगते हैं। इन जगहों पर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फिल्मी दुनिया में आ गए हैं। यहां की इमारतें, गलियां, कैफे और लोग सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जो आपको पूरी जिंदगी याद रहते हैं। वहीं फोटोग्राफी के लिहाज से भी यह जगहें बेस्ट हैं। अगर आप भी ऐसी जगहों की तलाश में हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

जयपुरः अगर भारत में कोई ऐसी जगह है, जो फिल्मी दुनिया का एहसास कराती है। यह राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर है। जयपुर शहर इतिहास, रंगों और रॉयल लुक से भरपूर है। यहां के किले, महल और हवेलियां में आपको बीते वक्त की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही रंग-बिरंगे कपड़े, भीड़-भाड़ वाले बाजार, मसाले और हस्तशिल्प हर गली को खास बनाते हैं। आपको जयपुर में सब कुछ गुलाबी देखने को मिलेगा। गुलाबी रंग की इमारतें और पारंपरिक डिजाइन इस शहर को वाकई फिल्मी एहसास देते हैं।

वेनिसः वैसे तो वेनिस एकदम सपनों का शहर लगता है और यहां का नजारा भी काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। आप यहां पर गोंडाला राइड करते समय डूबते हुए सूरज का शानदार नजारा देख सकते हैं। वहीं पानी में झलकती इमारतों को देखना किसी फिल्म जैसा अनुभव होता है।

सेंटोरिनी (ग्रीस): सफेद रंग के घर, नीले गुंबद वाले चर्च और समुद्र के किनारे बसा सेंटोरिनी शहर किसी रोमांटिक फिल्म की शूटिंग जैसा लगता है। सेंटोरिनी में सनसेट का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और यह शहर नेचुरल ब्यूटी का जीता जागता उदाहरण है।

रोम (इटली): जब भी खूबसूरत शहरों की बात होती है, तो सबसे पहले इटली का नाम लिया जाता है। इटली में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इटली का रोम शहर अपने आप बेहद शानदार है। ट्रेवी फाउंटेन, कोलोसियम और पुरानी गलियों वाला रोम हर एक पल को खास और फिल्मी बना देता है। यहां की ऐतिहासिक इमारतें भी किसी टाइम ट्रैवल का एक्सपीरियंस कराती हैं।

पेरिसः लोग पेरिस को 'City Of Love' कहते हैं। इस शहर की खूबसूरती आपको हर गली-नुक्कड़ पर देखने को मिलती है।

पेरिस की सीन नदी, एफिल टॉवर और पुराने पुल जैसे किसी फिल्म का सीन लगते हैं। पेरिस के छोटे-छोटे कैफे, शांत गलियां और सड़क पर कला दिखाते कलाकार हर पल को खास बना देते हैं।

दुबईः बता दें कि दुबई एक ऐसी जगह है, जहां पर जाने का सपना हर भारतीय का होता है। यहां की ऊंची इमारतें, चमकते मॉल और बुर्ज खलीफा इसको पूरी तरह से मॉर्डन फिल्म सेट जैसा बनाते हैं। रात की रोशनी और रेगिस्तान सफारी दुबई का यूनिक कॉम्बिनेशन है।

वीकेंड्स पर बनाएं जयपुर घूमने का प्लान, 3 दिन की यह ट्रिप रहेगी बेहद शानदार

राजस्थान में घूमने की बात आती है, तो सबसे पहले नाम आता है, चलो जयपुर घूमने चलते हैं। वीकेंड ट्रिप के लिए जयपुर से अच्छी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जयपुर एक ऐसा शहर है, जहां पर प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का परफेक्ट मेल देखने को मिलता है। इस शहर में आप ऐतिहासिक महल, किले, रॉयल लाइफ और लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2025 में जयपुर दुनियाभर के टॉप शहरों की लिस्ट में 5वां स्थान पर आया है। यहां पर घूमने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आप वीकेंड्स के दौरान ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। 3 दिन की ट्रिप के लिए बनाएं प्लान, इन जगहों करें एक्सप्लोर।

जयपुर में पहला दिन

ट्रिप के पहले दिन की शुरूआत आप जलमहल के शांत और खूबसूरत व्यू के साथ कर सकते हैं। सुबह की हल्की रोशनी इस जगह को बेहद खास बना देता है। इसके बाद पन्ना मीना कुंड देखने जाएं। इस कुंड में आपको पुरानी राजस्थानी बनावट के साथ शांत माहौल में समय बिताने का मौका मिलेगा। फिर आप यहां से आमेर फोर्ट जाएं, जहां आपको एकदम रॉयल फील जैसा लगेगा। अमेर फोर्ट बेहद ही सुंदर है, जिससे देखकर आप राजा-महाराजाओं की याद में खो जाएंगे। अब आप थोड़ा आराम कर लें। इसके बाद शाम को जगतशिरोमणि मंदिर जाएं और शांत माहौल में कुछ समय बिताएं। फिर आपको सबसे आखिरी में चोखी धानी में स्वादिष्ट राजस्थानी खाना खाएं और पारंपारिक माहौल के साथ करें।

ट्रिप का दूसरा दिन

दूसरे दिन जयपुर में आप सिटी पैलेस जाएं, जहां आपको राजघराने की कला और रॉयल लाइफ की झलक देखने को मिलेगी। इसके बाद आप सीधा जंतर-मंतर जाएं। इसके बाद हवा महल की सैर करें और इसकी खूबसूरती को नजदीक से फील करें। अगर आपके पास थोड़ा समय है, तो आप टैटू फैफे में बैठकर, जहां से आपको हवामहल की ऊंचाई देखने को मिलेगी। ध्यान रहे कि शाम होने से पहले नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच जाएं क्योंकि यहां से दिखने वाला सूर्यास्त यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाएगा। यदि आपको समय मिले तो वापसी में रात के समय हवामहल को बाहर से देखें, रात की रोशनी में बहुत ही सुंदर नजर आता है।

ट्रिप का तीसरा

तीसरे दिन सबसे पहले आप पत्रिका गेट और तोरण द्वार जरुर देखने जाएं। यहां की रंगीन दीवारें और सुंदर डिजाइन फोटो लेने के लिए एकदम परफेक्ट जगह हैं। फिर आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जाएं, जहां आपको राजस्थान की कला, इतिहास और कई अनोखी चीजें देख सकते हैं।

इसके बाद आप, यहां से गलताजी मंदिर जाएं, जो पहाड़ियों के बीच बना एक शांत और पवित्र स्थान है। अगर आप और घूमना चाहते हैं, तो गेटोर की छतरियों की ओर जाएं, जहां आप राजस्थानी वास्तुकला देखने के मिलेगी। ट्रिप के अंत में आप बापू बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं।

रात के सोते समय पैर बायटा आने पर क्या करें? आजमाएं यह देसी नुस्खा

डॉ. निमित त्यागी

रात के समय जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं, तो अचानक से पैर की तेज ऐंठन या 'बायटा' आने से चीखने लगते हैं। इस भयंकर दर्द में ऐसा लगता है कि किसी ने मांसपेशी को जोर से मरोड़ दिया हो। यह दर्द कुछ सेकंड का होता है, लेकिन इसका असर कई घंटों तक बना रहता है। रात की ऐंठन केवल दर्द नहीं, बल्कि शरीर में मिनरल्स की कमी, थकान, डिहाइड्रेशन या नर्व सिग्नल के गड़बड़ होने का संकेत भी हो सकती है, हालांकि इस परेशानी का आसान, तुरंत असर करने वाला और पूरी तरह नेचुरल इलाज आपकी अपनी रसोई में मौजूद है। इस देसी नुस्खे की मदद से आपको काफी आराम मिलेगा।

रात की ऐंठन केवल दर्द नहीं, बल्कि शरीर में मिनरल्स की कमी, थकान, डिहाइड्रेशन या नर्व सिग्नल के गड़बड़ होने का संकेत भी हो सकती है, हालांकि इस परेशानी का आसान, तुरंत असर करने वाला और पूरी तरह नेचुरल इलाज आपकी अपनी रसोई में मौजूद है। इस देसी नुस्खे की मदद से आपको काफी आराम मिलेगा।

बायटा के लिए देसी नुस्खा

आपको बता दें कि, यह देसी नुस्खा शरीर पर लगाने के लिए है, न कि इसे खाने के लिए। यह उपाय पैर के दर्द को दूर करने के साथ पूरे शरीर की नसों और मांसपेशियमों को आराम पहुंचाता है।

सामग्री

- शुद्ध देसी घी- 1 चम्मच
- नारियल का तेल- 1 चम्मच

कैसे इस्तेमाल करें

- देसी घी और नारियल के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर हल्का गुनगुना करें।
- इस मिश्रण को आप पैरों और हाथों के नाखूनों के सिरों पर लगाएं।
- नाखूनों की मालिश करने के बाद, पैरों के तलवों और जहां ऐंठन आई है, वहां हल्के हाथों से मालिश करें।
- रात को सोने से पहले रोज मालिश करने से बायटा आने का खतरा कम हो जाता है।

पैरों में ऐंठन के लिए यह देसी नुस्खा कैसे काम करता है?

- तंत्रिका तंत्र को शांत करना: इस देसी नुस्खा का इस्तेमाल करने से पैरों के तलवों में मौजूद तंत्रिका सिरों को उत्तेजित करती हैं, जो सीधा दिमाग को संदेश भेजते हैं कि अब मांसपेशियों को आराम करना है।
- ब्लड सकुर्लेशन अच्छा होता है: मालिश करने से उस हिस्से में ब्लड का सकुर्लेशन तेज होता है, जिससे मांसपेशियों में जमा हुआ लैक्टिक एसिड, जो कि ऐंठन का मुख्य कारण है, यह तेजी से बाहर निकल जाता है।
- घी का पोषण: देसी घी ऊतकों (टिश्यू) के गहरा पोषण देता है और वात कंट्रोल भी होता है, जिस वजह से दर्द और ऐंठन का अहम कारण है।
- कूलिंग नारियल तेल: नारियल तेल में कूलिंग गुणों मौजूद होते है, जो सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है।

इस मिश्रण से टू-इन-वन फायदे

- जब इस मिश्रण को रात के समय मालिश करते हैं, तो यह आपकी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है।
- इसके इस्तेमाल से आप तनाव कम होता है, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आती है।
- यह नाखूनों और स्किन को भी स्वस्थ रखता है।

घर के सदाबहार फूल में छुपा है डायबिटीज कंट्रोल का राज, ऐसे करें सेवन

डॉ. मुकुल शर्मा

सदाबहार का फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सदाबहार की पत्तियां और फूलों में एल्कलॉइड पाया जाता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसको डाइट में कैसे शामिल करना है।

डायबिटीज को कंट्रोल करने में सही डाइट का मुख्य रोल होता है। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर बढ़ता है और यदि आप मीठा खाना छोड़ देते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भले ही मीठा खाने या न खाने से ब्लड शुगर लेवल पर इसका असर होता है, लेकिन यह डायबिटीज को मैनेज करने के लिए काफी नहीं होता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में कई फल-फूल, सब्जियां और मसाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन्हीं में से एक सदाबहार का फूल है। यह फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सदाबहार की पत्तियां और फूलों में एल्कलॉइड पाया जाता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसको डाइट में कैसे शामिल करना है और यह ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करता है।

डायबिटीज कंट्रोल करेगा सदाबहार का फूल

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो सदाबहार यानी की कैथेरेन्थस रोजियस एक साधारण पौधा है। लेकिन यह साधारण सा पौधा ब्लड शुगर को बैलेंस करने में सहायता करता है। इसमें एल्कलॉइड्स इंसुलिन पाया जाता है, जो कि सेंसिटिविटी को सुधारते हैं और इससे पेनक्रियाटिक सेल्स को प्रोटेक्शन मिलता है। सदाबहार की फूल और पत्तियां सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाने में सहायता करता है।

इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं, जोकि ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं। वहीं इसके सेवन से इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ता है। इनके सेवन से बीटा-पैंक्रियाद सेल्स से इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है और यह बॉडी को डिटॉक्स करने में सहायता करता है और इससे खून भी साफ होता है।

सदाबहार के फूल और पत्तियों को डाइट में करें शामिल

बता दें कि खाली पेट सदाबहार के फूल की दो-तीन पत्तियों को चबाना चाहिए। रोजाना सदाबहार की पत्तियों का 1-2 चम्मच जूस पिएं।

इसके अलावा आप 1-2 सदाबहार के फूल को पानी में उबालकर इसको दिन में 1 बार पिएं।

सदाबहार की पत्तियों का पाउडर दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए।

सदाबहार के फूल और पत्तियों को इस तरह से डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि इनका अधिक मात्रा में सेवन न करें, साथ ही सही डाइट पर भी ध्यान दें।

बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद सफल एक्ट्रेस...

श्रद्धा कपूर

आज के दौर में श्रद्धा कपूर बॉक्स ऑफिस के लिए एक बेहद सफल एक्ट्रेस मानी जाती है। पिछले 6 साल से उनकी हर फिल्म बॉक्स तहलका मचाती रही है। इस दरमियान उन्होंने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। पिछले साल आई उनकी फिल्म 'स्त्री 2' (2024) ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। 'स्त्री 2' (2024) की शानदार कामयाबी के बाद श्रद्धा कपूर अब उसके अगले पार्ट वाली फिल्म 'स्त्री 3' में नजर आएंगी। सूत्रों की मानें तो उनकी यह फिल्म फ्रेंचाइजी के पहल दो पार्ट के मुकाबले ज्यादा मजेदार होने वाली है। 'स्त्री 3' से पहले उनकी एनीमेशन फिल्म 'छोटी स्त्री' आएगी। कहा जा रहा है कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'नो एंट्री' के सीक्वल के लिए श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया है हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'नागिन' में भी नजर आने वाली हैं। उनकी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज है। पंकज पाराशर द्वारा निर्देशित फिल्म 'चालबाज इन लंदन' में श्रद्धा कपूर लीड रोल निभाते नजर आने वाली हैं लेकिन अभी इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑफीशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है।

श्रद्धा कपूर ने अपनी स्कूलिंग जमनाबाई नरसी स्कूल से की। 15 साल की उम्र में वह अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में शिफ्ट हो गईं. यहां वह टाइगर श्रॉफ और अथिया शेट्टी की स्कूलमेट्स थीं। श्रद्धा जब 17 साल की थीं तब उन्हें सलमान खान ने अपनी एक प्रोडक्शन फिल्म में एक रोल ऑफर किया था हालांकि उस समय श्रद्धा ने सलमान खान का ऑफर ठुकरा दिया था। दरअसल वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थीं. श्रद्धा ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था।

पढाई पूरी करने के बाद नौकरी शुरू कर दी थी लेकिन अपनी पहली फिल्म तीन पत्ती में काम करने के लिए पहले साल में ही नौकरी छोड़ दी थी। श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'तीन पत्ती' (2010) से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद वो 'लव का द एंड' (2011) 'आशिकी 2' (2013), 'एक विलेन' (2014), 'हैदर' (2014), 'एबीसीडी 2' (2015), 'बागी' (2016), 'रॉक ऑन 2' (2016), 'हाफ गर्लफ्रेंड' (2017), 'स्त्री' (2018), 'साहो' (2019), 'छिछोरे' (2019), 'बागी 3' (2020) 'तू झूठी मैं मक्कार' (2023) और 'स्त्री 2' (2024) जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। फिल्म 'गोरी तेरे प्यार में' (2013) में श्रद्धा कपूर का पहला कैमियो एपीरियेंस था। उसके बाद उन्होंने 'उंगली' (2014), 'ए फ्लाइंग जट' (2016) 'नवाबजादे' (2018) और 'भेड़िया' (2022) जैसी फिल्मों के स्पेशल डांस नंबर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कभी एक्टर-डायरेक्टर फरहान अख्तर के साथ श्रद्धा कपूर की नजदीकियां काफी सुर्खियों में रहीं लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। फरहान अख्तर से अलग होने के बाद साल 2018 से श्रद्धा कपूर ने लगभग दो साल तक सेलेब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ को डेट किया था। लेकिन आजकल श्रद्धा कपूर राइटर राहुल मोदी के साथ अपनी डेटिंग और ब्रेक-अप की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। खुद श्रद्धा कंफर्म कर चुकी हैं कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं।

राहुल मोदी श्रद्धा कपूर की फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' (2023) के राइटर थे और कथित तौर पर फिल्म के निर्माण के दौरान दोनों करीब आए थे हालांकि पिछले दिनों इस तरह की भी खबरें आई थीं कि श्रद्धा और राहुल का ब्रेकअप हो चुका है।

बॉलीवुड की फेमस अदाकारा सुष्मिता सेन 18 की उम्र में ही बन गई थीं मिस यूनिवर्स

बॉलीवुड की फेमस अदाकारा सुष्मिता सेन ने 19 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन बनाया। सुष्मिता सेन ने महज 18 साल की उम्र में दुनियाभर में देश का नाम रोशन किया था। एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। बॉलीवुड की फेमस अदाकारा सुष्मिता सेन आज यानी की 19 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं। सुष्मिता सेन ने महज 18 साल की उम्र में दुनियाभर में देश का नाम रोशन किया था। एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं रही। अभिनेत्री हमेशा अपने शर्तों पर खूबसूरत जिंदगी जी रही हैं। वहीं महज 24 साल की उम्र में एक्ट्रेस बिन ब्याही मां बन गईं। एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में कई एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

जन्म और परिवार: हैदराबाद में 19 नवंबर 1975 को सुष्मिता सेन का जन्म हुआ था। एक्ट्रेस के पिता का नाम शुबीर सेन था, जोकि एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर थे। वहीं उनकी मां का नाम सुभ्रा सेन था। वह एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं।

मिस यूनिवर्स का ताज: वहीं 18 साल की उम्र में सुष्मिता सेन ने फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता था। इसके बाद साल 1994 में उन्होंने 19 साल की उम्र में भारत देश की पहली मिस यूनिवर्स बनीं। फिलीपींस के पासे में एक्ट्रेस ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया था और दुनियाभर में देश का नाम रोशन किया था। वहीं साल 2016 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स की जज भी बनीं।

फिल्मी सफर: साल 1996 में सुष्मिता सेन ने फिल्म 'दस्तक' हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। सुष्मिता सेन को साल 1999 में आई फिल्म 'बीवी नंबर 1' से असली पहचान मिली। यह डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म के लिए सुष्मिता सेन को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।

पर्सनल लाइफ: साल 2000 में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपनी पहले बेटी रेने सेन को गोद लिया और वह बिन ब्याही मां बन गईं। इसके बाद एक्ट्रेस ने साल 2010 में अपनी दूसरी बेटी अलीशा को गोद लिया। वहीं साल 2024 में सुष्मिता सेन को आखिरी बार साल आई फिल्म 'आर्या 3' में देखा गया था।

डेटिंग लाइफ: एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपनी पर्सनल लाइफ को कभी छिपाने की कोशिश नहीं की है। फिर चाहे वह एक्ट्रेस की डेटिंग लाइफ क्यों न हो। जब भी मोहब्बत की बात आई, तो उन्होंने उम्र को बाधा नहीं बनने दिया। सुष्मिता ने खुद से 15 साल छोटे मॉडल रोहमान शॉल को डेट कर चुकी हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस का नाम संजय नारंग, विक्रम भट्ट, रणदीप हुड्डा और ललित मोदी के साथ जुड़ चुका है।

वनडे रैंकिंग में बड़ा बदलाव

रोहित शर्मा से छीनी बादशाहत, किवी खिलाड़ी मिशेल बने नंबर वन

आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखा गया। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल शानदार प्रदर्शन के दम पर पहली बार नंबर 1 बन गए, जबकि रोहित शर्मा एक स्थान फिसलकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इब्राहिम जादरान की रैंकिंग घटी, वहीं बाबर आजम और श्रेयस अय्यर को फायदा मिला।

महमूद रजा
बिजनौर

आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टीम इंडिया के दिग्गज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पहले स्थान से खिसककर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी जगह न्यूजीलैंड के मजबूत बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। खास बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ एक अंक का फर्क है, इसलिए आने वाली रैंकिंग में फिर बदलाव संभव है। वहीं कई अन्य खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पाकिस्तान के बाबर आजम को भी हल्का फायदा हुआ है।

डेरिल मिचेल पहली बार वनडे में टॉप पर पहुंचे

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने इस बार आईसीसी वनडे रैंकिंग में इतिहास रच

दिया है। वे पहली बार दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ ताजा वनडे मैच में उन्होंने 119 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। इसी दमदार प्रदर्शन का उन्हें बड़ा फायदा मिला। आईसीसी की नई रैंकिंग में मिचेल को दो स्थान का फायदा हुआ और अब उनकी रेटिंग 782 अंक पहुंच गई है, जो उनके करियर की अब तक की सबसे ऊंची रेटिंग है। यह उपलब्धि न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए भी खास है, क्योंकि वनडे रैंकिंग में हाल के समय में न्यूजीलैंड के कम ही बल्लेबाज टॉप पर पहुंचे हैं।

रोहित शर्मा को रैंकिंग में हुआ नुकसान

टीम इंडिया के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा इस बार एक स्थान फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनकी रेटिंग 781 अंक है, यानी मिचेल से सिर्फ 1 अंक कम। यह मामूली अंतर बताता है कि अगर रोहित अगले वनडे मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मिचेल का प्रदर्शन औसत रहता है, तो रोहित दोबारा टॉप स्थान हासिल कर सकते हैं। रोहित पिछले कुछ महीनों से लगातार शानदार फॉर्म में हैं, जिसकी वजह से वे लंबे समय बाद वनडे बल्लेबाजी में फिर से नंबर 1 बने थे। लेकिन इस हफ्ते रैंकिंग में मामूली गिरावट आई है।

इब्राहिम जादरान की रैंकिंग में गिरावट

अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को इस बार एक स्थान का नुकसान हुआ है। वे तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और उनकी रेटिंग 764 अंक है। वहीं भारत के दो स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और विराट कोहली अपनी-अपनी चौथी और पांचवीं रैंक पर बने हुए हैं। गिल की पिछली सीरीजों में निरंतर प्रदर्शन की

वजह से उनकी रैंकिंग मजबूत बनी हुई है। विराट कोहली भी लिस्ट में स्थिर बने हुए हैं और टॉप-5 में शामिल रहने वाले दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं।

बाबर आजम को मिला फायदा

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को इस बार थोड़ा फायदा हुआ है। उन्हें एक स्थान की बढ़त मिली है और वे 622 अंक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में वे लगातार रन नहीं बना सके थे जिसके कारण उनकी रैंकिंग नीचे आ गई थी, लेकिन इस सप्ताह उन्हें हल्का सुधार मिला है। बाबर दुनिया के उन बल्लेबाजों में से हैं जो हर रैंकिंग चक्र में मजबूत वापसी की क्षमता रखते हैं।

श्रेयस अय्यर की रैंकिंग में बढ़त

टीम इंडिया के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। वे इस बार एक स्थान ऊपर बढ़कर नंबर 8 पर आ गए हैं और उनके रेटिंग पॉइंट 700 हो गए हैं। श्रेयस लगातार टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए हैं। वहीं श्रीलंका के चरित असलंका को तीन स्थान का भारी नुकसान झेलना पड़ा है और वे अब नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के भरोसेमंद खिलाड़ी शे होप अभी भी अपनी नंबर 10 की पोजिशन बनाए हुए हैं।

TCL

Global TOP 1 Mini LED TV Brand
by the shipment market share of Mini LED TVs in 2024

TCL GRAND DIWALI DHAMAKA

This Diwali, Buy a TCL 55 Inch or above
QD Mini LED TV & Win Exciting Prize!

55 Starts From ₹ 45,990* Less Cashback* (T&C*)

C6K *PREMIUM* QD-Mini LED TV

ROHIT SHARMA
BRAND AMBASSADOR, TCL INDIA

Weekly Treats
40 Weekly Winners will win E-Gift Vouchers for Festive Feasts

Scan to Enter

Festive Getaway
20 Winners will win Flight Ticket Vouchers for Holiday Journeys

Festive Bonus
10 winners will win an Exclusive Meet & Greet with Rohit Sharma*

Valid From Sep 20th - Oct 26th

TCL Premium Mini LED TV & QLED TV Range

C6KS — TCL *PREMIUM* QD-Mini LED TV

True Colors, True Details

185 cm (75) | 160.8 cm (65) | 136 cm (55)

55 Starts From ₹ 43,990* Less Cashback* (T&C*)

P7K — TCL *PREMIUM* QLED TV

Vivid and Vibrant

185 cm (75) | 160.8 cm (65) | 136 cm (55) | 126.5 cm (50) | 107.5 cm (43)

43 Starts From ₹ 25,990* Less Cashback* (T&C*)

NEW SERIES FOR 2025

P6K — TCL *PREMIUM* 4K HDR TV

Crystal Clear, Brilliantly Smart

185 cm (75) | 160.8 cm (65) | 136 cm (55) | 107.5 cm (43)

43 Starts From ₹ 21,990* Less Cashback* (T&C*)

S4K — TCL QLED TV

Restore true colours, see the world unfiltered

81.2 cm (32)

32 Starts From ₹ 11,990* Less Cashback* (T&C*)

S5K — TCL QLED TV

Restore true colours, see the world unfiltered

81.2 cm (32) | 107.5 cm (43)

43 Starts From ₹ 18,990* Less Cashback* (T&C*)

T&C Apply*

Available at

All Leading Consumer Electroinc Shops in Uttar Pradesh

UP West - Sunil Sharma : 9910349974
Lucknow Branch - Juned : 7897554445
Varanasi Branch - Ramkumar : 9838109000

All Leading Consumer Electroinc Shops in Haryana

Suresh Chandra : 7011099802

All Leading Consumer Electroinc Shops in Delhi & NCR

Sanjay David : 9871270725

All Leading Consumer Electroinc Shops in Punjab

Sanjay Kurana : 9780041403

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

Assuring Excellence in Bath Faucets

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

अविलंब ई-केवाईसी कराएं

सुगमता से खाद्यान्न पाएं

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत

समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की

ई-केवाईसी अनिवार्य

31 अगस्त, 2025 तक ई-केवाईसी न कराने वाले राशन कार्ड लाभार्थियों को सितम्बर, 2025 से आगामी 03 माह तक अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराने तक का अधिकतम समय रहेगा।

ऐसे लाभार्थियों को एस.एम.एस. के माध्यम से ई-केवाईसी कराए जाने का रिमाइंडर प्रेषण।

उक्त तीन माह में भी राशन कार्डधारकों को अपनी ई-केवाईसी कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसे लाभार्थियों द्वारा अपनी ई-केवाईसी कराने के उपरांत ही उन्हें, आगामी माह से राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

नवविवाहित/विवाहित महिलाओं के लिए, ई-केवाईसी की विशेष सुविधा उपलब्ध। ऐसी महिलाओं हेतु विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन यूनिट स्थानान्तरण का विकल्प उपलब्ध।

उक्त विकल्प के माध्यम से विवाहित महिलाओं द्वारा ससुराल के राशन कार्ड में यूनिट स्थानान्तरण किये जाने का आवेदन स्वयं करने की सुविधा।

ऑनलाइन आवेदन न कर पाने वाली महिलाओं को यूनिट ट्रांसफर हेतु आपूर्ति कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा।

---

05 वर्ष से कम उम्र के राशन कार्ड लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराए जाने से छूट।

नए राशन कार्ड से संबंधित सभी सदस्यों या प्रचलित राशन कार्ड में जोड़ी गयी नयी यूनिट को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा।

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP